वर्ष 12 • अंक 246 • 12 पृष्ठ • मूल्य 5 रुपये

मंगलवार 3 दिसंबर 2019

कोलकाता, चंडीगढ़, **नई दिल्ली**, पटना, भोपाल, मुंबई, रायपुर और लखनऊ से प्रकाशित।

भारत का पहला संपूर्ण हिंदी आर्थिक अखबार

# बिज़नेस स्टैंडर्ड

www.bshindi.com

पृष्ठ 2

निवेशक येस बैंक पर आशंकित

एस नरेन ▸▸ पृष्ठ 3

मजबूत बुनियाद है बाजार में तेजी का आधार

डॉलर रु. 71.70 (अपरिवर्तित) | यूरो रु. 78.90 (अपरिवर्तित) | सोना (10ग्राम) रु 37827 ▼ 40 रुपये | सेंसेक्स 40802.20 ▲ 08.40 | निफ्टी 12048.20 ▼ 07.80 | निफ्टी फ्यूचर्स 12091.50 ▲ 43.20 | ब्रेंट क्रूड 61.70 डॉलर ▲ 0.40 डॉलर

## एक नज़र

### विनिर्माण गतिविधियां बढ़ीं मगर रफ्तार धीमी

देश में विनिर्माण क्षेत्र की गतिविधियों में नवंबर में थोड़ा सुधार हुआ लेकिन नए ऑर्डर और उत्पादन में गहमा-गहमी की कमी से कुल मिला कर इस क्षेत्र की वृद्धि दर अभी धीमी बनी हुई है। औद्योगिक क्षेत्र के एक प्रतिष्ठित मासिक सर्वेक्षण में यह बात सामने आई है। आईएचएस मार्किट इंडिया विनिर्माण परचेजिंग मैनेजर्स सूचकांक (पीएमआई) नवंबर में बढ़ कर 51.2 रहा। अक्टूबर में पीएमआई 50.6 अंक पर दो वर्ष के न्यूनतम स्तर पर था। पृष्ठ 4

### उज्जीवन के आईपीओ को पहले दिन ही पूरा अभिदान

उज्जीवन स्मॉल फाइनैंस बैंक के आईपीओ को पहले दिन सोमवार को 1.7 गुना आवदेन प्राप्त हुए। खुदरा निवेशकों के लिएए आरक्षित श्रेणी में करीब 9 गुना बोलियां मिलीं। हालांकि खुदरा निवेशकों के लिए महज 10 फीसदी शेयर आरक्षित रखे गए हैं जबकि सामान्य तौर पर इस श्रेणी के लिए 35 फीसदी शेयर रखे जाते हैं। निर्गम का मूल्य दायरा 36 से 37 रुपये प्रति शेयर रखा गया है।

### रियल एस्टेट ग्रुप के पास 3,000 करोड़ रु. काला धन

एनसीआर के एक रियल एस्टेट ग्रुप ने 3,000 करोड़ रुपये से अधिक का काला धन होने की बात स्वीकार की है। सीबीडीटी ने सोमवार को बताया कि समूह के 25 ठिकानों पर आय कर विभाग ने पिछले सप्ताह छापा मारा गया था। हालांकि उसने इसके नाम का खुलासा नहीं किया लेकिन सूत्रों ने दावा किया है कि यह ओरियंटल इंडिया ग्रुप है।

### आरबीआई को बनाया जा सकता है पक्षकार

आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्याधिकारी चंदा कोछड़ ने अपनी बर्खास्तगी और बोनस व स्टॉक आप्शंस की वापसी के मामले में भारतीय रिजर्व बैंक को पक्षकार बनाने के लिए बंबई उच्च न्यायालय से समय मांगा। इस पर अदालत ने याचिका को संशोधित करने व आरबीआई को नोटिस भेजने के लिए उन्हें 9 दिसंबर तक का समय दे दिया। पृष्ठ 3

### भूल सुधार

28 नवंबर को 'सेबी संग मामला निपटाएगा बैंक' शीर्षक से प्रकाशित समाचार के संदर्भ में आईसीआईसीआई बैंक ने स्पष्ट किया है कि उसकी सहमति याचिका दायर करने की कोई योजना नहीं है। उसने यह भी कहा कि उसे बाजार नियामक की तरफ से कोई नया कारण बताओ नोटिस नहीं मिला है। त्रुटि के लिए खेद है।

**आज का सवाल**

**क्या एनएसडीएल के कदम से कार्वी के ऋणदाताओं की बढ़ेगी मुश्किल**

www.bshindi.com **पर राय भेजें।**
आप अपना जवाब एसएमएस भी कर सकते हैं। यदि आपका जवाब हां है तो **BSP Y** और यदि न है तो **BSP N** लिखकर **57007** पर भेजें।

**पिछले सवाल का नतीजा**

| क्या कॉल दरें बढ़ाने से सुधरेगी दूरसंचार क्षेत्र की सेहत? | |
|---|---|
| हां | 70.00% |
| नहीं | 30.00% |

# मैट कटौती इसी वित्त वर्ष से

## लोकसभा ने कराधान संशोधन बिल को दी मंजूरी, सरकार राजकोषीय घाटे से वाकिफ

**दिलाशा सेठ और अरूप रायचौधरी**
नई दिल्ली, 2 दिसंबर

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज स्पष्ट किया कि सितंबर में घोषित न्यूनतम वैकल्पिक कर (मैट) की घटी दर इसी वित्त वर्ष से लागू होंगी। कराधान संशोधन विधेयक में एक गलती के कारण कंपनियां असमंजस में थीं।

सीतारमण ने लोकसभा में इस विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए राजकोषीय अनुशासन बनाए रखने की चुनौतियों के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा कि राजकोषीय घाटे के बारे में अंतिम फैसला संशोधित अनुमानों में लिया जाएगा। लोकसभा ने इस विधेयक को मंजूरी दे दी। लोकसभा में इसी सत्र में पेश विधेयक में कहा गया था कि मैट की 15 फीसदी दर वर्ष 2020-21 से लागू होगी जबकि अध्यादेश में कहा गया था कि इसी वित्त वर्ष में घटी दर लागू हो जाएगी। इस विसंगति को दूर करने के लिए आधिकारिक संशोधन लाया गया और वित्त वर्ष बदलकर 2019-20 कर दिया गया।

सीतारमण ने कहा, 'हमारी मंशा हमेशा यही रही है कि मैट की घटी दर वित्त वर्ष 2019-20 से लागू हो। अब इस आधिकारिक संशोधन के जरिये इसे त्रुटि को दूर किया जाएगा।' देश में विकास और निवेश को बढ़ावा देने तथा विनिर्माण क्षेत्र में नया निवेश आकर्षित करने के लिए सरकार ने अध्यादेश के जरिये घरेलू कंपनियों को विकल्प दिया कि अगर वे कटौती और छूट का दावा न करें तो उन्हें 22 फीसदी की दर से कर देना होगा। छूट लेने वाली कंपनियों पर मैट की दर 18.5 फीसदी से घटाकर 15 फीसदी कर दी। अगर किसी कंपनी की सामान्य कर देनदारी सभी तरह की कटौतियों का लाभ उठाने के बाद एक निश्चित सीमा से नीचे रहती है तो उस स्थिति में उसे न्यूनतम कर का भुगतान करना होता है। नई दरें अपनाने वाली कंपनियों को भी मैट क्रेडिट का भी लाभ नहीं मिलेगा।

नांगिया एंडर्सन कंसल्टिंग में मैनेजिंग पार्टनर राकेश नांगिया कहते हैं, 'सरकार ने मैट दरें लागू होने की तिथियों में तालमेल का अभाव दूर कर लिया है। कम मैट दर 1 अप्रैल 2019 से लागू होगी, जो स्वागत योग्य कदम है। तिथियों में मेल-जोल नहीं होने से असमंजस की स्थिति पैदा हो गई थी और वित्त मंत्री के स्पष्टीकरण के बाद इसे दूर कर लिया गया है।'

सीतारमण ने कहा, 'सदस्यों द्वारा राजकोषीय घाटे पर उठाई गई चिंता का मैं पूरा सम्मान करती हूं। कॉर्पोरेट करों में कमी किए जाने के बाद सरकार को करीब 1.45 लाख करोड़ रुपये राजस्व का मोह त्यागना होगा। सरकार संशोधित अनुमान जारी करने के समय राजकोषीय घाटे पर अंतिम निर्णय लेगी।' सीतारमण ने कहा कि संप्रग-2 के समय औसत राजकोषीय घाटा 5.5 प्रतिशत रहा था, जबकि मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में यह जीडीपी का 3.68 प्रतिशत रहा था। उन्होंने कहा, 'हमने राजकोषीय अनुशासन दुरुस्त रखने के लिए सभी उपाय किए हैं और औसत राजकोषीय घाटा 4 प्रतिशत से नीचे रखा है।'

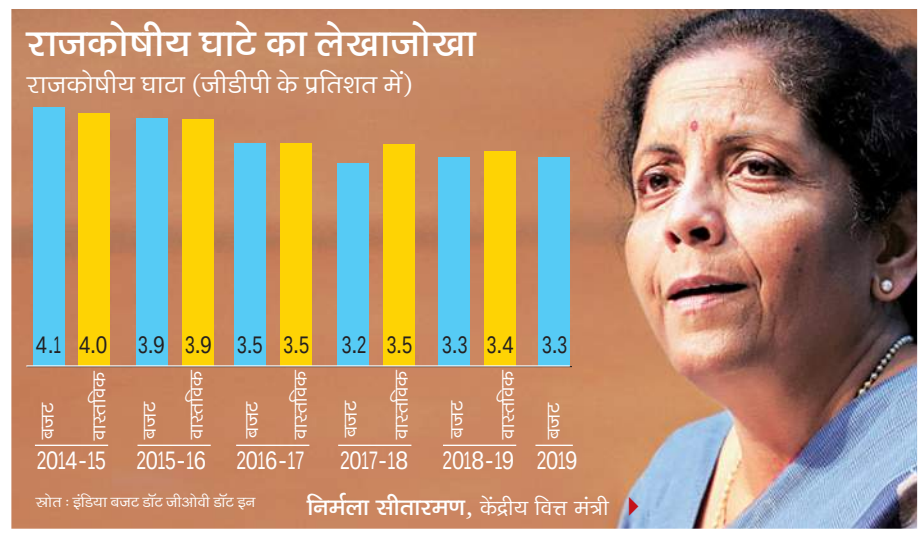


# शेयर हस्तांतरण पर सैट पहुंचे ऋणदाता

**समी मोडक और जश कृपलानी**
मुंबई, 2 दिसंबर

**कार्वी** समूह के लिए मुश्किलें और बढ़ती जा रही हैं। ब्रोकरेज के ऋणदाताओं ने नैशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी (एनएसडीएल) द्वारा ब्रोकरेज कंपनी के डीमैट खाते से ग्राहकों के खाते में प्रतिभूतियों को हस्तांतरित करने के निर्णय पर आपत्ति जताई है। डिपॉजिटरी ने निवेशकों के हितों की सुरक्षा की है, वहीं इन शेयरों को गिरवी रखकर कार्वी को कर्ज देने वाले ऋणदाताओं की परेशानी बढ़ गई है।

एनएसडीएल ने अपने बयान में कहा, 'सेबी के निर्देशों के अनुसार कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग के डीमैट खाते से प्रतिभूतियों को संबंधित ग्राहकों के खाते में हस्तांतरित कर दिया गया है। ऐसे ग्राहकों की संख्या 82,559 है।' बजाज फाइनैंस ने इस कदम को प्रतिभूति अपील पंचाट (सैट) में चुनौती दी है। सूत्रों के अनुसार एनबीएफसी दिग्गज ने कार्वी को 250 करोड़ रुपये का कर्ज दिया था। इस कर्ज को हासिल करने के लिए ब्रोकरेज ने अवैध तरीके से ग्राहकों की प्रतिभूतियों को अपने खाते में हस्तांतरित किया था। बजाज फाइनैंस का शेयर बीएसई पर आज 3 फीसदी से ज्यादा गिरावट पर बंद हुआ। सैट में इस मामले पर मंगलवार को सुनवाई हो सकती है।

विधि विशेषज्ञों का कहना है कि इस आदेश से शेयर के एवज में कर्ज की व्यवस्था पर व्यापक असर पड़ सकता है।

(शेष पृष्ठ 2 पर)

- एनएसडीएल ने कर्ज के एवज में गिरवी रखे शेयरों को ग्राहकों के खातों में किया हस्तांतरित
- बजाज फाइनैंस ने एनएसडीएल के कदम को सैट में दी चुनौती
- स्टॉक एक्सचेंजों ने 2 दिसंबर से निलंबित किया कार्वी का लाइसेंस
- ग्राहकों को खरीद-बिक्री के लिए अन्य ब्रोकर के पास खुलवाना होगा खाता

# दिल्ली में खुलेगा स्तरीय खेल विश्वविद्यालय

**एजेंसियां**
नई दिल्ली, 2 दिसंबर

**ओलंपिक** खेलों में अधिक से अधिक पदक जीतने के लिए राजधानी दिल्ली में खेल विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इस कदम का मकसद ओलंपिक खेलों में देश के लिए चीन से अधिक पदक जीतना है।

दिल्ली विधानसभा में आज खेल विश्वविद्यालय विधेयक ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। विधेयक पर चर्चा के दौरान केजरीवाल ने कहा कि प्रस्तावित विश्वविद्यालय का संचालन राजनेताओं और अफसरों द्वारा नहीं बल्कि पेशेवरों द्वारा किया जाएगा। केजरीवाल ने कहा कि पिछले 70 साल में देश ने ओलंपिक में केवल 28 पदक जीते हैं। भारत में प्रतिभा की कमी नहीं है बल्कि जरूरत है उन्हें बेहतर दिशा देने की। उन्होंने कहा, 'यह विधेयक हर युवा और खिलाड़ियों के सपनों को साकार करेगा और देश चीन के मुकाबले ज्यादा पदक हासिल करेगा। मेरा सपना है कि यह मेरे जीते जी पूरा हो।' उन्होंने कहा कि इस विश्वविद्यालय में दिल्ली के युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी, वहीं देश के प्रतिभाशाली युवाओं और खिलाड़ियों को भी यहां अवसर उपलब्ध होंगे।

### पानी के मुद्दे पर बहिर्गमन

विधानसभा में शीत सत्र के पहले दिन सोमवार को शहर में दूषित पानी के मुद्दे को लेकर विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता और विधायकों ने बहिर्गमन किया। उन्होंने इस विषय पर चर्चा की मांग की थी जिसे विधानसभा अध्यक्ष ने अस्वीकार कर दिया। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही गुप्ता और तीन भाजपा विधायकों मनजिंदर सिंह सिरसा, ओम प्रकाश शर्मा और जगदीश प्रधान दूषित पानी की बोतलें लाए, जिसकी कथित तौर पर शहर में आपूर्ति की जा रही है। उन्होंने वे बोतलें सदन में दिखाईं। विपक्ष ने इस विषय पर चर्चा की मांग की लेकिन विधानसभा अध्यक्ष राम निवास गोयल ने कहा कि वह सूचीबद्ध विषयों से इतर विषयों पर चर्चा की इजाजत नहीं देंगे।

# मांग में कमी से सिकुड़ रहा इस्पात उद्योग

**ईशिता आयान दत्त**
कोलकाता, 2 दिसंबर

**भारतीय** इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (सेल) के आईआईएससीओ (इस्को) स्टील प्लांट की पिछले महीने हुई एक बैठक में प्रत्येक विभाग से पूछा गया कि लागत में प्रति टन 3,500 रुपये की कटौती में उनका क्या योगदान होगा। जब तक हर विभाग ने इस बारे में प्रतिबद्धता नहीं जताई, किसी को भी बैठक से नहीं जाने दिया गया। बैठक शाम 5 बजे शुरू हुई और आधी रात तक चली।

**नरमी का असर**

इससे पता चलता है कि इस्को के मुख्य कार्याधिकारी ए वी कमलाकर लागत में कटौती के लिए कितने गंभीर हैं। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में स्थित इस संयंत्र का अगले महीने प्रति टन लागत में 1,500 रुपये कटौती का लक्ष्य है। सुस्त पड़े स्टील बाजार में मुनाफा बरकरार रखने का एकमात्र जरिया लागत में कटौती है। कमलाकर ने कहा कि पिछले एक साल के दौरान शुद्ध बिक्री से होने वाली प्राप्ति प्रति टन 10 हजार रुपये कम हो गई है। केवल पिछली तिमाही में ही इसमें प्रति टन 4,000 से 5,000 रुपये की गिरावट आई है।

**खपत कम, उत्पादन ज्यादा**

| वर्ष | उत्पादन | वृद्धि | खपत | वृद्धि |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 61.3 | – | 44.2 | – |
| 2018 | 49.2 | 4.4 | 48.4 | 7.8 |
| 2019 | 51.8 | 5.2 | 50.8 | 4.9 |

**वैश्विक मांग**

| वर्ष | आयात | वृद्धि | निर्यात | वृद्धि |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 4.3 | – | 4.8 | – |
| 2018 | 4.0 | -7.3 | 3.2 | -35.2 |
| 2019 | 4.0 | 0.4 | 3.9 | 21.8 |

आंकड़े प्रतिशत में, स्रोत : संयुक्त संयंत्र समिति

इस्को के वित्तीय प्रदर्शन में भी यह बात परिलक्षित होती है। सितंबर में समाप्त तिमाही में उसे 194.9 करोड़ रुपये का कर पूर्व नुकसान हुआ जबकि जून तिमाही में यह 60.9 करोड़ रुपये था। इस्को मुख्य रूप से निर्माण और बुनियादी क्षेत्र को आपूर्ति करता है जो मॉनसून, सरकारी खर्च में कमी और नकदी संकट के कारण बुरी तरह प्रभावित हुआ है। संयंत्र के वायर रॉड कॉइल का एक छोटा हिस्सा वाहनों के कलपुर्जे बनाने वाली कंपनियां भी इस्तेमाल करती हैं। इस क्षेत्र में भी कमजोर मांग के कारण संयंत्र की मुश्किलें बढ़ी हैं।

स्टील की कुल मांग में करीब 60 फीसदी हिस्सा निर्माण क्षेत्र का है जबकि 8 से 10 फीसदी हिस्सा वाहन क्षेत्र का है। स्टील के किसी बड़े एकीकृत संयंत्र में लागत में कटौती के लिए कच्चे माल के अलावा कुछ ही चीजों में बदलाव किया जा सकता है। एक अधिकारी ने कहा, 'कच्चा माल ही बदलने लायक है। अगर हम प्रति किलो कोक की दर समायोजित करें तो इससे करोड़ों रुपये की बचत होगी।'

इस्को की भट्ठी रोजाना पूरी क्षमता के साथ काम करने पर 7,800 टन इस्पात का उत्पादन करती है। सितंबर में उत्पादन 6,000 टन रहा और अक्टूबर में यह 6,700 टन था। अलबत्ता नवंबर में इसकी पूरी क्षमता बहाल हो गई। (शेष पृष्ठ 12 पर)

## खबरों में रहे स्टॉक

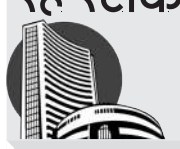

### भारती एयरटेल

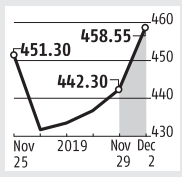


दूरसंचार ऑपरेटरों ने बढ़ाई दरें

₹ 442.30 पिछला बंद भाव
₹ 458.55 आज का बंद भाव
▲ 3.67 %

### आयशर मोटर्स

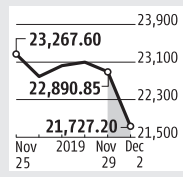


नवंबर में मोटरसाइकल की बिक्री 8 फीसदी घटी

₹ 22,890.85 पिछला बंद भाव
₹ 21,727.20 आज का बंद भाव
▼ 5.08 %

### येस बैंक

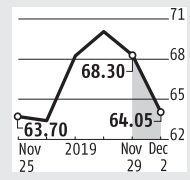


एसऐंडपी बीएसई सेंसेक्स में सबसे अधिक गिरने वाला शेयर

₹ 68.30 पिछला बंद भाव
₹ 64.05 आज का बंद भाव
▼ 6.22 %

### सुवेन लाइफ साइंसेज

दूसरे चरण में अल्जाइमर मॉलिक्यूल से निराशा

₹ 314.80 पिछला बंद भाव
₹ 264.70 आज का बंद भाव
▼ 15.91 %

### ऐस्ट्रजेनेका फार्मा इंडिया

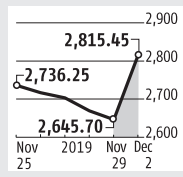


एमएनसी फार्मा शेयरों में सबसे अधिक चढ़ने वाला शेयर

₹ 2,645.70 पिछला बंद भाव
₹ 2,815.45 आज का बंद भाव
▲ 6.42 %

## संक्षेप में

### महिंद्रा फाइनैंस को मिलेगी आईएफसी से रकम

विश्व बैंक समूह की इकाई अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम (आईएफसी) ने महिंद्रा ऐंड महिंद्रा फाइनैंशियल सर्विसेज में करीब 20 करोड़ डॉलर यानी 1,433 करोड़ रुपये का निवेश करने की घोषणा की है। आईएफसी ने कहा है कि इस निवेश का मकसद कम आय वाले राज्यों में सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उपक्रमों (एमएसएमई) के वित्तपोषण के लिए विशिष्ट रूप से पूल बनाने का है। कम-से-कम 10 करोड़ डॉलर महिलाओं के स्वामित्व वाले एमएसएमई के लिए रखे जाएंगे। आईएफसी ने इसमें 7.5 करोड़ डॉलर का निवेश अपने खाते से किया है जबकि बाकी 12.5 करोड़ डॉलर की राशि समानांतर कर्ज से जुटाई जा रही है। वहीं महिंद्रा फाइनैंस ने इस कोष में अपनी तरफ से 22.5 करोड़ डॉलर डालने की प्रतिबद्धता जताई है। *भाषा*

### सनरा मीडिया व अफसरों पर सेबी ने लगाया जुर्माना

भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) ने ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स (जीडीआर) में गड़बड़ी के मामले में सनरा मीडिया लिमिटेड और उसके छह अधिकारियों पर 16 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। सेबी ने देश की ऐसी कई कंपनियों के खिलाफ जांच की थी जिन्होंने भारतीय निवेशकों को चूना लगाने के मकसद से विदेशी बाजारों में जीडीआर जारी किए थे। इस जांच के बाद यह आदेश आया है। नियामक ने अपनी जांच में पाया कि सनरा मीडिया भी उन कंपनियों में शामिल है जिसने जीडीआर के अंशधारकों द्वारा लिए गए कर्ज के लिए जीडीआर से अपनी प्राप्ति को लिस्बन के बैंक इफिसा एसएफ्ई में ऋण के एवज में गिरवी रखा था। *भाषा*

### उबर ने भारत में खोला अपना दूसरा उत्कृष्टता केंद्र

कैब एग्रीगेटर सेवा प्रदाता उबर ने अपना दूसरा इंडियन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस विशाखापट्टनम में खोला है जहां पर करीब 500 लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। करीब आठ लाख डॉलर की लागत से विकसित यह केंद्र तत्काल ध्यान देने की जरूरत वाले महत्त्वपूर्ण मामलों में विशेषीकृत ग्राहक सेवा प्रदान करेगा। *भाषा*

# निवेशक येस बैंक पर आशंकित

## बड़े निवेशकों का अभाव, रिजर्व बैंक की मंजूरी को लेकर सशंकित, शेयर टूटा

**हंसिनी कार्तिक और देव चटर्जी**
मुंबई, 2 दिसंबर

बड़े निवेशकों का अभाव और भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से नए निवेशकों के निवेश को मंजूरी न देने की आशंका ने येस बैंक के शेयर पर असर डाला और सोमवार को इसकी कीमत 6.2 फीसदी टूटकर 64 रुपये रह गई। फरवरी 2023 में परिपक्व होने वाला बैंक का डॉलर बॉन्ड भी दो महीने में रबसे ज्यादा टूटा।

शुक्रवार शाम बैंक ने ऐलान किया था कि उसका निदेशक मंडल निवेशकों से 2 अरब डॉलर जुटाने पर सहमत हो गया है और इसमें से 1.2 अरब डॉलर का निवेश कनाडा के कारोबारी इर्विन सिंह ब्रेच/ एसपीजीपी होल्डिंग्स से आएगा। दूसरा बड़ा निवेश सिटैक्स होल्डिंग्स से आएगा।

बैंक ने ब्रेच के नाम का खुलासा एक महीने से नहीं किया था जब उसने कहा था कि उसे एक निवेशक से बाध्यकारी पेशकश मिली है। कयास हालांकि बड़े व अहम निवेशकों के नाम से लगाए गए थे, लेकिन निवेशक ब्रेच के नाम से निराश हुए, जिन्हें भारत में वस्तुत: नहीं जाना जाता है।

62 वर्षीय इर्विन सिंह ब्रेच जब 20 साल के थे तब वे ब्रिटिश कोलंबिया की पढ़ाई छोड़कर अपने पिता के कारोबार का नियंत्रण अपने हाथ में लेने के आ गए। 2 जनवरी 2013 की मीडिया रिपोर्ट में कहा गया था कि बाद के वर्षों में उन्होंने अपने पारिवारिक कारोबार को अरबों डॉलर का बना दिया और प्रवासी भारतीय पिता के कारोबार को काफी आगे बढ़ाया। यह बयान तब जारी हुआ जब ब्रेच ने कनाडा के पब्लिक प्रॉसिक्यूशन सर्विस और रॉय कनाडा पुलिस के खिलाफ मुकदमा दायर किया। यह मुकदमा दिवालिया कार्यवाही से संबंधित मामूली आरोप के चलते उन्हें गिरफ्तार करने की धमकी के कारण था। यह पहला मौका नहीं था जब ब्रेच ने आरोप लगाया हो।

साल 2013 में जब वकील जमशेद मिस्त्री के हवाले से यह कहा गया कि ब्रेच के स्वामित्व वाले ट्रस्ट की शुद्ध कीमत उन्हें कनाडा में दूसरा सबसे अमीर व्यक्ति बनाता है और उन्हें दुनिया भर में तीन सबसे अमीर भारतीय में से एक बनाता है। मिस्त्री ने कहा था, लेकिन रतन टाटा की तरह ब्रेच अपनी कारोबारी गतिविधियां विभिन्न ट्रस्टों के जरिए चलाते हैं, लिहाजा अरबपति की किसी सूची में शामिल नहीं होते।

विश्लेषकों का कहा है कि प्रमुख विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने में येस बैंक की विफलता का एक कारण उसकी परिसंपत्ति गुणवत्ता को लेकर अनिश्चितता भी है। बैंक करीब एक साल से इससे जूझ रहा है। येस बैंक का सकल एनपीए अनुपात 7.4 फीसदी है जो निजी क्षेत्र के शीर्ष बैंकों में सबसे खराब परिसंपत्ति गुणवत्ता को दर्शाता है।

आरबीआई की जांच से पता चला है कि वित्त वर्ष 2019 में बैंक के एनपीए में 3,277 करोड़ रुपये का अंतर दिखा। इसमें से 632 करोड़ रुपये दिसंबर तिमाही में बनने के आसार हैं। इससे वित्त वर्ष 2020 के लिए प्रावधान की लागत बढ़ सकती है। ऐसे में निवेशकों को परिचालन जारी रखने के लिए अधिक रकम झोंकना पड़ेगा।

### निवेशकों को नुकसान

■ येस बैंक का शेयर मूल्य सोमवार को 6.2 फीसदी टूटकर 64 रुपये रह गया

■ फरवरी 2023 में परिपक्व होने वाला बैंक का डॉलर बॉन्ड भी दो महीने में रबसे ज्यादा टूटा

# डीएचएफएल: दिवालिया याचिका स्वीकार

**सुब्रत पांडा**
मुंबई, 2 दिसंबर

**नैशनल** कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) के मुंबई पीठ ने आवास वित्त कंपनी दीवान हाउसिंग फाइनैंस कॉरपोरेशन (डीएचएफएल) के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की ओर से दायर दिवालिया याचिका को आज स्वीकार कर लिया। डीएचएफएल ने भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) से ली गई वाह्य वाणिज्यिक उधारी (ईसीबी) के ब्याज भुगतान में चूक की थी।

डीएचएफएल ऐसी पहली वित्तीय सेवा कंपनी है जिसके खिलाफ एनसीएलटी में दिवालिया प्रक्रिया शुरू की जाएगी। सरकार ने 15 नवंबर को वित्तीय सेवाओं के लिए ऋण शोधन अक्षमता कानून को अधिसूचित किया था।

डीएचएफएल ने ईसीबी के जरिये एसबीआई से 24 करोड़ डॉलर जुटाए थे और यह रकम दो चरणों में जुटाई गई थी। पहले चरण में 11 करोड़ डॉलर और दूसरे चरण में 13 करोड़ डॉलर जुटाए गए थे। डीएचएफएल ने 21.6 लाख डॉलर के ब्याज भुगतान में चूक की थी जिसके बाद उसके खिलाफ दिवालिया याचिका दायर की गई थी। इस आवास वित्त कंपनी ने इसी साल जुलाई में गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर (एनसीडी) धारकों के पुनर्भुगतान में भी चूक की थी।

डीएचएफएल के खिलाफ इस मामले में एसबीआई मुख्य वित्तीय लेनदार है। हालांकि एनसीएलटी ने इस आवास वित्त कंपनी के खिलाफ दिवालिया याचिका को स्वीकार कर लिया है लेकिन ट्रिब्यूनल ने चिंता जताई कि कंपनी के पिछले प्रबंधन का कोई प्रतिनिधित्व नहीं था क्योंकि आरबीआई ने उसके बोर्ड को निलंबित कर दिया था। ट्रिब्यूनल ने देखा कि डीएचएफएल के खिलाफ आरबीआई की याचिका को चुनौती देने वाला कोई नहीं था।

आरबीआई ने 20 नवंबर को डीएचएफएल के बोर्ड को निलंबित कर इंडियन ओवरसीज बैंक के पूर्व सीएमडी आर सुब्रमण्यकुमार को प्रशासक नियुक्त किया था। तीन सदस्यीय सलाहकार समिति भी गठित की गई है। डीएचएफएल की कुल देनदारी सितंबर 2019 के अनुसार 92,715 करोड़ रुपये है जिसमें सुरक्षित ऋण 73,833 करोड़ रुपये और असुरक्षित ऋण 18,881 करोड़ रुपये है।

## दोपहिया वाहनों की बिक्री नवंबर में घटी

**वाहन** क्षेत्र में नरमी की मार दोपहिया वाहन बनाने वाली कंपनियों पर भी पड़ रही है। कमजोर मांग के कारण नवंबर 2019 में अधिकतर दोपहिया वाहन विनिर्माताओं ने बिक्री में गिरावट दर्ज की है। पिछले महीने हीरो मोटोकॉर्प की बिक्री में 15.31 फीसदी की गिरावट आई जबकि बजाज ऑटो की घरेलू बिक्री को करीब 11.5 फीसदी और टीवीएस मोटर की घरेलू बिक्री को 26.52 फीसदी का झटका लगा।

हीरो मोटोकॉर्प की कुल बिक्री पिछले महीने 15.31 फीसदी घटकर 5,16,775 वाहन रह गई। पिछले साल इसी माह में कंपनी की कुल बिक्री 6,10,252 वाहनों की रही थी। इस दौरान कुल मोटरसाइकल बिक्री 4,79,200 वाहन रही जो पिछले साल की इसी अवधि में बिके 5,43,982 वाहनों के मुकाबले कम है। स्कूटर की बिक्री 66,270 वाहनों से घटकर 37,575 वाहन रह गई। बजाज ऑटो की बिक्री पिछले महीने 0.9 फीसदी घटकर 4,03,223 वाहन रह गई जबकि पिछले साल नवंबर में कंपनी ने 4,06,930 वाहनों की बिक्री की थी। दोपहिया-तिपहिया वाहन विनिर्माता टीवीएस मोटर कंपनी की कुल बिक्री नवंबर में 16.64 फीसदी घटकर 2,66,582 वाहन रही। *एजेंसियां*

# वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री रफ्तार सुस्त

**टीई नरसिम्हन**
चेन्नई, 2 दिसंबर

**घरेलू** बाजार में वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री नवंबर 2019 में करीब 18 फीसदी घटकर 55,473 वाहन रह गई जो एक साल पहले की समान अवधि में 67,374 वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री हुई थी। पिछले महीने के मुकाबले प्रमुख कंपनियों के आंकड़े बेहतर हैं लेकिन औद्योगिक गतिविधियों में नरमी, मॉनसून के लंबा खिंच जाने से बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में देरी, परिचालन लागत में इजाफा आदि कारणों से मांग पर दबाव बरकरार है। हालांकि कंपनियों ने उम्मीद जताई है कि अगले वित्त वर्ष की दूसरी छमाही तक स्थिति में सुधार होनी चाहिए। वाणिज्यिक वाहन बनाने वाली देश की सबसे बड़ी कंपनी टाटा मोटर्स के वाणिज्यिक वाहनों की घरेलू बिक्री नवंबर 2019 में करीब 17 फीसदी घटकर 27,657 वाहन रह गई जबकि एक साल पहले यह आंकड़ा 33,488 वाहनों का था। इसमें मझोले एवं वाणिज्यिक वाहन (एमऐंडएचसीवी) की नवंबर 2019 में 6,050 वाहनों की बिक्री भी शामिल जिसमें पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 38 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई। पिछले साल नवंबर में 9,793 वाहनों की बिक्री हुई थी।

वाणिज्यिक वाहन बनाने वाली देश की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी अशोक लीलैंड के वाणिज्यिक वाहनों की घरेलू बिक्री (एमऐंडएचसीवी और एलसीवी सहित) नवंबर में 25 फीसदी घटकर 9,377 वाहन रह गई। पिछले साल की समान अवधि में कंपनी ने 12,570 वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री की थी। कंपनी के एमऐंडएचसीवी की बिक्री नवंबर में 36 फीसदी घटकर 5,321 वाहन रह गई जबकि पिछले साल नवंबर में 8,260 वाहनों की बिक्री हुई थी।

ट्रकों की बिक्री पिछले महीने 55 फीसदी घटकर 3,447 वाहन रह गई जबकि एक साल पहले की अवधि में 7,627 ट्रकों की बिक्री हुई थी। घरेलू बाजार में कंपनी की बसों की बिक्री 196 फीसदी बढ़कर 1,874 वाहन हो गई। पिछले साल की समान अवधि में यह आंकड़ा महज 633 बसों का रहा था। सरकारी खरीद के लिए ऑर्डर मिलने से बसों की बिक्री रफ्तार बढ़ी। महिंद्रा ऐंड महिंद्रा के वाणिज्यिक वाहनों की घरेलू बिक्री पिछले महीने 12 फीसदी घटकर 17,387 वाहन रह गई जबकि नवंबर 2018 में 19,673 वाहनों की बिक्री हुई थी।

## सैट पहुंचे कार्वी के लेनदार

**पृष्ठ 1 का शेष...**

**सूत्रों** ने कहा कि अन्य ऋणदाता भी एनएसडीएल की कार्रवाई के खिलाफ सैट जा सकते हैं। ब्रोकरेज ने प्रतिभूतियों को गिरवी रखकर आईसीआईसीआई बैंक, इंडसइंड बैंक और एचडीएफसी बैंक से कर्ज लिए हैं।

कार्वी पर गलत तरीके से करीब 95,000 ग्राहकों की 2,300 करोड़ रुपये मूल्य की प्रतिभूतियों को गिरवी रखकर करीब 600 करोड़ रुपये का कर्ज लेने का आरोप है। एनएसडीएल ने कार्वी के ग्राहकों के करीब 87 फीसदी प्रतिभूतियां हस्तांतरित कर दी हैं। हालांकि ये शेयर उन्हीं ग्राहकों को वापस किए गए हैं जिनका कोई बकाया नहीं था। इस कदम से ऋणदाताओं के पास कर्ज के लिए अब कोई जमानत नहीं बची है।

इस बीच स्टॉक एक्सचेंजों ने नियमों का अनुपालन नहीं करने की वजह से कार्वी के ब्रोकिंग कारोबार का लाइसेंस भी निलंबित कर दिया है। एक्सचेंज की ओर से जारी परिपत्र में कहा गया है, 'नैशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) ने नियामकीय प्रावधानों का पालन नहीं करने की वजह से कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग का लाइसेंस 2 दिसंबर से निलंबित किया जाता है।' एनएसई के बाद बंबई स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) ने भी उसका ब्रोकिंग लाइसेंस निलंबित कर दिया।

बीएसई ने कहा, 'एक्सचेंज ने कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग के ट्रेडिंग सदस्यों के टर्मिनल्स को निष्क्रिय कर दिया है। इससे वे इक्विटी एवं डेट खंड में कारोबार नहीं कर पाएंगे। इसके साथ ही उन्हें इक्विटी डेरिवेटिव, मुद्रा डेरिवेटिव और जिंस खंड में आरआरएम मोड डाल दिया है।' कार्वी द्वारा ग्राहकों के पैसों के दुरुपयोग के खिलाफ सेबी के आदेश के बाद एक्सचेंजों ने यह कार्रवाई की है।

# दूरसंचार फर्मों का खाता होगा दुरुस्त

## शुल्क दरें बढ़ने से एयरटेल और वोडाफोन-आइडिया के परिचालन लाभ में 7,000-9,500 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी की उम्मीद

**राम प्रसाद साहू और मेघा मनचंदा**
मुंबई/नई दिल्ली, 2 दिसंबर

देश की बड़ी दूरसंचार सेवा प्रदाता कंपनियों ने अपनी कॉल एवं डेटा शुल्क दरों में बढ़ोतरी की जो घोषणा की है उससे भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और रिलायंस जियो के परिचालन लाभ में खासी तेजी आने की उम्मीद है। एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ने अपनी नई योजनाओं के शुल्क औसतन 30 फीसदी तक बढ़ा दिए हैं और नई दरें मंगलवार से प्रभावी हो रही हैं। वहीं जियो ने भी अपनी दरों में 40 फीसदी तक वृद्धि के संकेत देते हुए कहा है कि नई दरें 6 दिसंबर से लागू हो जाएंगी। जियो ने अभी तक सेगमेंट के हिसाब से नई दरों की घोषणा नहीं की है।

उम्मीद है कि नई शुल्क दरें लागू होने पर भारती एयरटेल एवं वोडा-आइडिया का प्रति उपभोक्ता औसत राजस्व (एआरपीयू) 30 रुपये तक बढ़ जाएगा। इससे दोनों कंपनियों के वार्षिक परिचालन लाभ में भी 7,000-9,500 करोड़ रुपये तक की वृद्धि होने की संभावना जताई जा रही है। दूरसंचार ऑपरेटरों के संगठन भारतीय सेल्युलर ऑपरेटर संघ (सीओएआई) का मानना है कि बढ़ी दरें एयरटेल और वोडाफोन आइडिया के एआरपीयू को करीब पांच साल पहले के स्तर पर पहुंचा देंगी। संघ के महानिदेशक राजन मैथ्यूज ने कहा, 'कंपनियों ने एक सकारात्मक कदम उठाया है जिससे उन्हें कुछ समय के लिए समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) के भुगतान के बरक्स समर्थन मिलेगा।'

(वित्त वर्ष 2021 के लिए अनुमान)

| कंपनी | औसत राजस्व प्रति ग्राहक पुराना | नया | बदलाव (% में) |
|---|---|---|---|
| वोडाफोन आइडिया | 111 | 149 | 34.2 |
| भारती एयरटेल | 139 | 176 | 26.6 |
| रिलायंस जियो | 144 | 159 | 10.4 |

स्रोत : एमके रिसर्च

विश्लेषकों का आकलन है कि दरें बढ़ाने से जियो को भी फायदा पहुंचेगा लेकिन कंपनी की तरफ से नई दरें घोषित नहीं होने से उसके वित्तीय लाभ के बारे में अनुमान लगा पाना मुश्किल है। कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज के विश्लेषकों ने कहा है कि जियो की संशोधित योजनाओं में '300 फीसदी अधिक मुनाफे' जैसे दावों के चलते कंपनी को होने वाले सापेक्षिक मूल्य लाभ का आकलन कर पाना मुश्किल है।

प्री-पेड योजनाओं में की गई मूल्य-वृद्धि के अनुमान से अधिक होने की वजह से दूरसंचार कंपनियों के शेयरों में तेजी देखी गई। कारोबार के दौरान वोडाफोन आइडिया और भारती एयरटेल के शेयर 7-18 फीसदी तक चढ़ गए जबकि रिलायंस इंडस्ट्रीज में 2.5 फीसदी तेजी रही। दोनों कंपनियों के नए मूल्य ढांचे से भी उन्हें फायदा हुआ है। कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज के रोहित चोर्डिया एवं अनिकेत सेठी का मानना है कि वोडा-आइडिया एवं एयरटेल ने कारोबार में संभावित गिरावट (डाउनट्रेडिंग) को ध्यान में रखते हुए एंट्री स्तर की डेटा पेशकश और लोकप्रिय योजनाओं में बड़ा फासला रखा है। डेटा उपभोक्ताओं के लिए डाउनट्रेडिंग का मतलब काफी मूल्य छोड़ना होगा जबकि अपट्रेडिंग से खासा बढ़ा हुआ मूल्य मिलेगा।

शुल्क दरें बढ़ने से सिम कार्ड बदलने के साथ ग्राहकों के उद्वेलित होने की भी आशंका पैदा हो सकती है। एमके ग्लोबल के नवल सेठ का कहना है कि शुल्क बढ़ने एवं सिम सशक्तीकरण भारती एयरटेल और रिलायंस जियो के लिए सकारात्मक होंगे जबकि वोडाफोन आइडिया के अब भी नेटवर्क एकीकरण के दौर में होने से वह अनुमानित सीमा से अधिक ग्राहकों और राजस्व बाजार हिस्सेदारी को खो सकती है।

### आईसीआईसीआई बैंक के खिलाफ चंदा की याचिका

# अदालत ने दी आरबीआई को पक्षकार बनाने की अनुमति

**सुब्रत पांडा**
मुंबई, 2 दिसंबर

**आईसीआईसीआई बैंक** की पूर्व प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्याधिकारी चंदा कोछड़ ने अपनी बर्खास्तगी और बोनस व स्टॉक आप्शंस की वापसी के मामले में भारतीय रिजर्व बैंक को पक्षकार बनाने के लिए बंबई उच्च न्यायालय से समय मांगा। इस पर अदालत ने याचिका को संशोधित करने व आरबीआई को नोटिस भेजने के लिए उन्हें 9 दिसंबर तक का समय दे दिया। इस मामले पर अगली सुनवाई 9 दिसंबर को होगी।

कोछड़ की याचिका पर आईसीआईसीआई बैंक ने अपने जवाब में कहा है कि आरबीआई ने मार्च 2019 में कोछड़ की बर्खास्तगी मामले पर आगे बढ़ने को कहा था, वहीं बैंक ने उन्हें बर्खास्तगी का पत्र जनवरी 2019 में दिया।

कोछड़ के वकील ने तर्क दिया कि बैंकिंग नियमन अधिनियम की धारा 35 बी के मुताबिक, किसी बैंक के चेयरमैन या प्रबंध निदेशक का अनुबंध समाप्त करने के लिए आरबीआई की पूर्व अनुमति की जरूरत होती है। लेकिन इस मामले में आरबीआई की मंजूरी बैंक की तरफ से बर्खास्तगी पत्र दिए जाने के बाद मिली।

इस धारा में कहा गया है, जब तक आरबीआई की पूर्व अनुमति नहीं मिल जाती कोई भी चेयरमैन, प्रबंध निदेशक या पूर्णकालिक निदेशक, प्रबंधक या मुख्य कार्याधिकारी की नियुक्ति, पुनर्नियुक्ति या बर्खास्तगी प्रभावी नहीं होगी।

एक वकील ने कहा, बैंक के सीईओ व एमडी की नियुक्ति और बर्खास्तगी के सभी मामलों में आरबीआई की अनुमति तब सामने आती है जब बोर्ड ऐसी नियुक्तियों को मंजूरी देकर नियामक की इजाजत मांगता है। बैंक ने कोछड़ को बर्खास्त करने की अनुमति आरबीआई से उसके बाद मांगी जब 4 अक्टूबर 2018 को कोछड़ ने इस्तीफा भेजा और बोर्ड ने उसे स्वीकार कर लिया। बैंक ने इस साल जनवरी में आरबीआई से कोछड़ को बर्खास्त करने की अनुमति मांगी जब बोर्ड को पूर्व न्यायाधीश बी एन कृष्णा की रिपोर्ट मिली, जिसमें कोछड़ को दोषी ठहराया गया था।

दूसरी ओर आईसीआईसीआई बैंक ने कोछड़ की याचिका को चुनौती दी है और कहा है कि कोछड़ की बर्खास्तगी अनुबंध का मामला है और आईसीआईसीआई बैंक निजी बैंक है, लिहाजा यह याचिका स्वीकार करने योग्य नहीं है।

पिछले साल मीडिया की खबरों में जब वीडियोकॉन समूह को दिए कर्ज मामले में कोछड़ पर सवाल उठाया गया था तब बैंक के निदेशक मंडल ने शुरू में चंदा का बचाव किया था और बाहरी जांच को ठुकरा दिया था। लेकिन सीबीआई की तरफ से जांच शुरू किए जाने के बाद अपना रुख बदल लिया था। 6 जून 2018 को बैंक ने सर्वोच्च न्यायालय के अवकाशप्राप्त न्यायाधीश बी एन कृष्ण को इस मामले की जांच सौंपी थी।

कोछड़ ने अक्टूबर 2018 में रिटायर होने का विकल्प चुना और बैंक के बोर्ड ने इसकी मंजूरी दी। हालांकि जनवरी 2019 में बैंक ने उन्हें पद से बर्खास्त कर दिया।

## संक्षेप में

### ऐक्सिस बैंक ने पेश किया प्राइवेट बैंकिंग प्लेटफॉर्म

ऐक्सिस बैंक ने आज प्राइवेट बैंकिंग प्लेटफॉर्म बुरुगुंडी प्राइवेट पेश किया, जो धनाढ्य व अति-धनाढ्य ग्राहकों के सेवाएं देगा। बुरुगुंडी प्राइवेट फैमिली ऑफिस को संपत्ति प्रबंधन और उधार का समाधान, शोध आधारित सलाह, एस्टेट प्लानिंग, रियल एस्टेट और कर सलाह की पेशकश करेगी। इस मौके पर ऐक्सिस बैंक के प्रबंध निदेशक व सीईओ अमिताभ चौधरी ने कहा, जब अर्थव्यवस्था 5 लाख करोड़ डॉलर के करीब पहुंचेगी तब धनाढ्य लोगों की संपत्ति का आधार भी तेज गति से बढ़ने का अनुमान है। दिलचस्प रूप से यह बढ़त न सिर्फ प्रमुख मेट्रो शहरों को सम्मिलित करेगा बल्कि छोटे व मझोले शहरों को भी। इस प्लेटफॉर्म के जरिए हमारी योजना ऐसे बड़े मौके को भुनाने की है। बीएस

### सामी होटल्स को मिली आईपीओ लाने की मंजूरी

सामी होटल्स को बाजार नियामक सेबी से आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) के जरिए पूंजी बाजार से 1,800 से 2,000 करोड़ रुपये जुटाने की मंजूरी मिल गई है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार कंपनी ने सितंबर में सेबी के पास आईपीओ के लिए दस्तावेज जमा कराए थे। कंपनी को सेबी से टिप्पणी मिल गई है। कंपनी के मसौदा पत्र के अनुसार साम्ही होटल के आईपीओ में 1,100 करोड़ नए शेयर तथा 1,91,45,624 शेयरों की बिक्री पेशकश शामिल है। सूत्रों के अनुसार निर्गम का आकार 1,800 से 2,000 करोड़ रुपये के बीच हो सकता है। कंपनी आईपीओ के जरिए प्राप्त राशि का उपयोग कर्ज लौटाने तथा सामान्य कंपनी कामकाज में करेगी। *भाषा*

# अदालत से एवरेडी व मैकलॉयड को राहत

**अभिषेक रक्षित**
कोलकाता, 2 दिसंबर

कलकत्ता उच्च न्यायालय से बीएम खेतान समूह को राहत मिली है क्योंकि समूह की कंपनियों मैकलॉयड रसेल और एवरेडी इंडस्ट्रीज की तरफ से संपत्ति बिक्री पर लगी अस्थायी रोक अदालत ने हटा ली। एवरेडी अपनी जमीन बेच रही है जबकि मैकलॉयड चाय बागान बेच रही है ताकि कर्ज घटाया जा सके। साथ ही एवरेडी अपने ड्राई-सेल कारोबार की बिक्री के लिए ड्यूरासेल समेत अन्य बैटरी निर्माताओं से बातचीत कर रही है।

पिछले आदेश में इन कंपनियों को अपनी परिसंपत्तियां बेचने से रोका गया था, लेकिन उच्च न्यायालय ने ताजा आदेश में दोनों कंपनियों को अपने कर्ज घटाने की योजना बनाने का रास्ता साफ कर दिया। मैकलॉयड के लेनदारों ने एसबीआई कैप्स को कर्ज पुनर्गठन योजना लाने को कहा है और एलएसआई फाइनैंशियल को पुनर्गठित कर्ज के भुगतान की मैकलॉयड की क्षमता जांचने के लिए नियुक्त किया गया है, अगर लेनदार इस पर सहमति जताते हों।

सूत्रों ने हालांकि कहा था कि मैकलॉयड के लिए लेनदारों की योजना में न सिर्फ कर्ज पुनर्गठन शामिल है बल्कि इसमें कर्ज चुकाने के लिए चाय बागान बेचकर रकम जुटाने का मामला भी शामिल हो सकता है।

सूत्रों ने कहा कि जिन विकल्पों पर विचार हो रहा है उनमें 800 करोड़ रुपये तक के कर्ज के पुनर्गठन, पुनर्भुगतान की अवधि का विस्तार और बागानों की बिक्री शामिल है, जिससे 200 करोड़ रुपये से लेकर 400 करोड़ रुपये मिल सकते हैं। पुनर्गठन योजना बनाने में शामिल रहे अन्य प्रोफेशनल का कहना है कि और चाय बागान बेचे बिना मैकलॉयड के लिए करीब 1,700 करोड़ रुपये कर्ज चुकाना मुश्किल होगा।

एलएसआई पहले ही लेनदारों को प्राथमिक रिपोर्ट सौंप चुकी है और एसबीआई कैप्स की रिपोर्ट की प्रतीक्षा हो रही है, जिसके आधार पर वह अंतिम मसौदा जमा करेगी।

# कार्वी फिनटेक ने बदला नाम, नए चेयरमैन नियुक्त

**मूल कंपनी** से जुड़े विवाद से खुद को अलग करने के लिए जनरल अटलांटिक की हिस्सेदारी वाली कार्वी फिनटेक ने अपना नाम बदलकर केफिन टेक्नोलॉजिज कर लिया है। प्राइवेट इक्विटी दिग्गज के पास करीब एक साल से केफिन टेक्नोलॉजिज की नियंत्रक हिस्सेदारी है। केफिन टेक ने एमवी से वित्त पोषित कंपनियों के सलाहकार हैं।

पिछले हफ्ते कार्वी समूह के चेयरमैन व प्रबंध निदेशक सी पार्थसारथि ने केफिनटेक से इस्तीफा दे दिया था, जो 26 लाख करोड़ रुपये वाले म्युचुअल फंड उद्योग के लिए रजिस्ट्रार व ट्रांसफर एजेंट के तौर पर काम करती है। *बीएस*

नायर को तत्काल प्रभाव से कंपनी का गैर-कार्यकारी चेयरमैन नियुक्त किया है। नायर अभी ट्रांसयूनियन सिबिल के चेयरमैन और भारत में प्राइवेट इक्विटी व वेंचर कैपिटल

### बीएस बातचीत

# मजबूत फंडामेंटल हैं शेयर बाजार की तेजी का आधार

पिछले हफ्ते शेयर बाजार रिकॉर्ड ऊंचाई को छू गया और रिलायंस इंडस्ट्रीज 10 लाख करोड़ रुपये के बाजार पूंजीकरण पर पहुंचने वाली पहली भारतीय सूचीबद्ध कंपनी बन गई। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ऐसेट मैनेजमेंट के कार्यकारी निदेशक और मुख्य निवेश अधिकारी **एस नरेन** ने **पुनीत वाधवा** को दिए साक्षात्कार में कहा कि लंबी अवधि के लिहाज से लार्जकैप के मुकाबले मिडकैप व स्मॉलकैप बेहतर है। मुख्य अंश...

**पिछले हफ्ते बाजार रिकॉर्ड ऊंचाई को छू गया। इस पृष्ठभूमि में आप खुदरा निवेशकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या उन्हें इक्विटी में अभी भी आवंटन बढ़ाना चाहिए?**
अभी निवेशकों को परिसंपत्ति आवंटन के अनुशासन पर ध्यान देना चाहिए। न सिर्फ इक्विटी बल्कि डेट में भी निवेशित बने रहना महत्वपूर्ण है। इक्विटी में अगर कोई निवेशक पांच साल से ज्यादा समय तक निवेशित रहने के लिए तैयार है तो वह मिडकैप व स्मॉलकैप, वैल्यू और मल्टीकैप में चरणबद्ध तरीके से निवेश पर विचार कर सकता है। इसकी वजह यह है कि इन क्षेत्रों का मूल्यांकन अपेक्षाकृत आकर्षक है। इसी तरह डेट में भी हम लगातार सकारात्मक बने हुए हैं क्योंकि मूल्यांकन आकर्षक है।

**क्या बाजार फंडामेंटल से आगे चल रहा है? बाजार के लिए वित्त वर्ष 2020 कैसा रहेगा?**
कंपनी कर घटाने के सरकारी फैसले, अच्छे मॉनसून और केंद्रीय बैंक के कदमों से बाजार का फंडामेंटल सुधरा है और इस वजह से वैश्विक इक्विटी में भी तेजी आई है। बाजार हालांकि सस्ते नहीं हैं, लेकिन मजबूत फंडामेंटल इस तेजी का आधार है। अल्पावधि के लिहाज से बाजार का परिदृश्य बताना मुश्किल है क्योंकि गुणवत्ता वाले नाम महंगे बने हुए हैं।

**इस चरण में बाजार के मूल्यांकन को लेकर आप कितने सहज हैं?**
लार्जकैप में तेजी के बाद मूल्यांकन को पूरी तरह समाहित किया गया है, लेकिन आय में सुधार को अभी रफ्तार पकड़ना बाकी है। इक्विटी बाजार का मौजूदा प्रदर्शन चुनिंदा शेयरों में बढ़ोतरी के चलते है। बढ़त और वैल्यू वाले शेयरों के मूल्यांकन के बीच जुड़ाव न होने से हमारा मानना है कि अल्पावधि में वैल्यू व विशेष परिस्थिति वाली थीम अपना असर दिखाएगी। अभी गुणवत्ता वाले नाम महंगे हैं। लंबी अवधि के लिहाज से लार्जकैप के मुकाबले मिडकैप व स्मॉलकैप बेहतर हैं।

**जीडीपी के ताजा आंकड़ों ने चौंकाया है। आर्थिक मंदी पर चल रही पूरी बहस को आप कैसे देखते हैं?**
कारोबारी चक्र अभी संकुचन के चरण में है, जिसे विभिन्न आंकड़ों मसलन निजी उपभोग, हवाई परिवहन के आंकड़े और कर्ज की रफ्तार में देखे जा सकते हैं। जीडीपी के आंकड़े भी मंदी का संकेत दे रहे हैं। जहां तक उपभोग से जुड़ी कंपनियों में मंदी की बात है, मौजूदा प्रवृत्ति अल्पावधि में बनी रह सकती है। हमारा मानना है कि मौजूदा आर्थिक माहौल में राजकोषीय घाटा शायद ही बड़ी समस्या होगी।

**बढ़त दर को रफ्तार पकड़ने में कितना वक्त लगेगा।**
हमारा मानना है कि बढ़त धीरे-धीरे जोर पकड़ेगा क्योंकि हम निचले स्तर के करीब हैं। बाजार का अनुमान है कि सरकार लाभांश वितरण कर और वैयक्तिक कर में कटौती जैसे सुधार के कदम उठाएगी।

**पिछले हफ्ते रणनीतिक विनिवेश की सरकारी घोषणा के बाद सरकारी उपक्रमों को लेकर क्या राय है?**
सरकारी उपक्रमों के शेयर अभी आकर्षक मूल्यांकन पर उपलब्ध हैं। हमारा मानना है कि सरकार रणनीतिक विनिवेश जारी रखेगी।

**किन क्षेत्रों पर आप ओवरवेट और अंडरवेट हैं?**
वित्त वर्ष 2020 की दूसरी तिमाही के नतीजे के सीजन में कोई बड़ी निराशा नहीं देखने को मिली है। हम अभी बिजली, दूरसंचार, धातु व खनन क्षेत्र को लेकर ओवरवेट हैं। हम बैंक और वित्तीय क्षेत्र, उपभोक्ता (गैर-टिकाऊ) और सॉफ्टवेयर पर अंडरवेट हैं।

## संक्षेप में

### क्रिसिल ने वृद्धि अनुमान 5.1 प्रतिशत किया

वित्तीय साख निर्धारित करने वाली एजेंसी क्रिसिल ने चालू वित्त वर्ष में भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर के अपने अनुमान को काफी कम कर 5.1 प्रतिशत कर दिया है। इससे पूर्व में उसने वृद्धि 6.3 प्रतिशत रहने का अनुमान जताया था। अन्य एजेंसी डन ऐंड ब्राड स्ट्रीट ने कहा है कि निकट भविष्य में भारत की आर्थिक वद्धि दर नरम बनी रह सकती है। क्रिसिल का यह अनुमान जापान की ब्रोकरेज कंपनी नोमुरा के 4.7 प्रतिशत अनुमान के बाद सबसे कम है। रेटिंग एजेंसी ने जीडीपी वृद्धि का आंकड़ा आने के कुछ दिन बाद ही यह अनुमान जताया है। *भाषा*

### एचएएल में हड़ताल 5 को खत्म होने की उम्मीद

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हिंदुस्तान एयरोनोटिक्स लिमिटेड (एचएएल) की 14 अक्टूबर से चल रही हड़ताल एचएएल प्रबंधन के साथ संभावित सहमति पत्र (एमओयू) पर हस्ताक्षर होने के साथ ही पांच दिसंबर को खत्म होने का सोमवार को भरोसा दिलाया। सिंह ने राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान कहा कि कर्मचारी संगठन और एचएएल प्रबंधन के बीच अब तक 13 दौर की बैठक के बाद पांच दिसंबर को अंतिम दौर की बैठक होगी। उन्होंने इसमें कर्मचारियों की मांगों को लेकर दोनों पक्षों के बीच विभिन्न मुद्दों पर सहमति बनने का हवाला देते हुए कहा कि पांच दिसंबर की बैठक में एमओयू पर हस्ताक्षर होने की पूरी उम्मीद है। *भाषा*

### अयोध्या फैसले पर पुनर्विचार याचिका दायर

अयोध्या में विवादित स्थल पर राम मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त करने वाले उच्चतम न्यायालय के 9 नवंबर के फैसले पर पुनर्विचार के लिए सोमवार को एक मुस्लिम पक्षकार ने याचिका दायर की। तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाले 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने अयोध्या में 2.77 एकड़ विवादित भूमि राम लला को सौंपने और मस्जिद निर्माण के लिए उप्र सुन्नी वक्फ बोर्ड को पांच एकड़ का भूखंड आवंटित करने का केन्द्र को निर्देश दिया था। हालांकि, संविधान पीठ के इस फैसले को उप्र सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने चुनौती नहीं देने का निर्णय लिया लेकिन इस प्रकरण के मूल वादकारों में शामिल एम सिद्दीक के कानूनी वारिस और उप्र जमीयत उलेमा-ए-हिन्द के अध्यक्ष मौलाना सैयद अशहाद रशीदी ने 14 बिन्दुओं पर शीर्ष अदालत के निर्णय पर पुनर्विचार के लिए याचिका दायर की है। *भाषा*

### ऐतिहासिक रूस-चीन गैस पाइपलाइन की शुरुआत

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने सोमवार को दोनों देशों के बीच पहली गैस पाइपलाइन से गैस आपूर्ति की शुरुआत की। ऐतिहासिक कदम मानी जा रही यह गैस पाइपलाइन दोनों देशों के बीच बनाई गई है। इस दौरान पुतिन ने कहा, 'आज का दिन खास है। यह सिर्फ वैश्विक ऊर्जा बाजार के लिए ही नहीं बल्कि हमारे और आपके लिए, रूस और चीन सभी के खातिर एक ऐतिहासिक अवसर है।' *भाषा*

### ई सिगरेट पर प्रतिबंध को संसद की मंजूरी

युवाओं और बच्चों को ई सिगरेट के खतरे से बचाने के लिए इसे प्रतिबंधित करने वाले विधेयक को सोमवार को संसद की मंजूरी मिल गई। राज्यसभा ने इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट (उत्पादन, विनिर्माण, आयात, निर्यात, परिवहन, विक्रय, वितरण, भंडारण और विज्ञापन) प्रतिषेध विधेयक, 2019 को पारित कर दिया। लोकसभा इसे पिछले सप्ताह ही पारित कर चुकी है। *भाषा*

### पेट्रोल व डीजल पर कर कटौती का प्रस्ताव नहीं

सरकार ने सोमवार को कहा कि पेट्रोल एवं डीजल पर कर में कटौती का कोई प्रस्ताव नहीं है। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों के उत्तर में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह टिप्पणी की। उन्होंने यह भी कहा कि दुनिया में कहीं एक निश्चित समय के लिए पेट्रोल एवं डीजल के दाम स्थिर नहीं होते हैं। *भाषा*

# निजीकरण योजना के साथ सरकार

**अरूप रॉयचौधरी**
नई दिल्ली, 2 दिसंबर

नरेंद्र मोदी सरकार एयर इंडिया, भारत पेट्रोलियम, कॉनकॉर और शिपिंग कॉर्पोरेशन जैसी सरकारी कंपनियों की 'रणनीतिक बिक्री' के रुख से नहीं हटी है, भले ही स्वदेशी जागरण मंच जैसे उससे जुड़े संगठन इस कदम का विरोध और उसकी लगातार आलोचना कर रहे हैं।

सोमवार को एक शीर्ष अधिकारी ने बिजनेस स्टैंडर्ड को बताया, 'प्रधानमंत्री कार्यालय ने यह साफ किया है कि टीएचडीसी और नीपको को छोड़कर सभी अन्य कंपनियों का निजीकरण किया जाएगा और उन्हें निजी कारोबारियों को बेचा जाएगा। आशय स्पष्ट है, सीसीईए ने इसकी मंजूरी दे दी है और हम इस प्रक्रिया की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।'

निवेश एवं सार्वजनिक उद्यम विभाग बीपीसीएल, कॉनकोर और शिपिंग कॉर्पोरेशन के लिए लेन देन और कानूनी सलाहकार नियुक्त करने की प्रक्रिया में है। मिल रही जानकारी के मुताबिक बीपीसीएल और कॉनकॉर के लिए डेलॉयट को लेन देन सलाहकार नियुक्त किया गया है। बीपीसीएल के निजीकरण के लिए जे सागर एसोसिएट्स को कानूनी सलाहकार नियुक्त किया गया है, वहीं कॉनकॉर के लिए लूथरा ऐंड लूथरा को नियुक्त किया गया है। सूत्रों ने कहा कि शिपिंग कॉर्पोरेशन के लिए नियुक्ति पर अगला फैसला होना है।

अधिकारियों ने कहा कि नियुक्तियां इस बात की संकेत हैं कि नौकरशाही केंद्र की प्रतिबद्धता की दिशा में आगे बढ़ रही है। उपरोक्त उल्लिखित अधिकारी ने कहा, 'इस तरह के सभी लेन देन राजनीति शोर से जुड़े हैं। हमारा लक्ष्य तय प्रक्रिया का पालन करना और यह सुनिश्चित करना है कि सरकार को इन सौदों से संभावित बेहतर मूल्य मिल सके।'

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) से जुड़े स्वदेशी जागरण मंच ने सरकारी उपक्रमों के रणनीतिक विनिवेश के मोदी सरकार के फैसले को अविवेकी कारोबारी फैसला करार दिया है, जो राष्ट्रीय हितों के खिलाफ है।

इस माह की शुरुआत में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की थी कि नरेंद्र मोदी सरकार भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल), द कंटेनर कॉर्पोरेशन आफ इंडिया (कॉनकॉर) और शिपिंग कॉर्पोरेशन आफ इंडिया सहित 5 सरकारी उपक्रमों की रणनीतिक हिस्सेदारी बिक्री करेगी और इन फर्मों के प्रबंधन के नियंत्रण का हस्तांतरण किया जाएगा।

स्वदेशी जागरण मंच ने हरिद्वार में आयोजित अपने राष्ट्रीय सम्मेलन में बीपीसीएल और एयर इंडिया जैसी कंपनियों के रणनीतिक विनिवेश पर सवाल उठाया। मंच ने मांग की थी कि नीति आयोग की विनिवेश पर रिपोर्ट को खारिज किया जाना चाहिए और सरकारी कंपनियों के मूल्य व उनकी जरूरत पर नए सिरे से आकलन करने की जरूरत है।

मंच के राष्ट्रीय सह संयोजक अश्विनी महाजन ने कहा, 'सरकारी उपक्रमों का रणनीतिक विनिवेश न सिर्फ अविवेकी कारोबारी फैसला है, बलिल्क यह राष्ट्रीय हित के भी खिलाफ है।' उन्होंने कहा, 'यह न सिर्फ भारत के लोगों को खारिज करने वाला है, जो सरकारी उपक्रमों के असल मालिक हैं, बल्कि इनके संभावित खरीदारों को अनुचित लाभ पहुंचाने वाला फैसला है।'

पिछले महीने मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने बीपीसीएल, शिपिंग कॉर्पोरेशन, टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड और नीपको लिमिटेड में केंद्र की पूरी हिस्सेदारी बेचने और कंटेनर कॉर्पोरेशन में बहुलांश हिस्सेदारी बेचने और इन कंपनियों का प्रबंधन छोड़ देने का फैसला किया था।

**बिकेंगी सरकारी कंपनियां**

सूचीबद्ध इकाइयों कॉनकॉर और एससीआई से **20,817** करोड़ रुपये मिलने की उम्मीद

**5** रोड शो ईवाई और दीपम के अधिकारियों ने एयर इंडिया के निजीकरण के लिए हाल में मुंबई, सिंगापुर और लंदन में किए

- **1.05** करोड़ रुपये का विनिवेश लक्ष्य हासिल करने में बीपीसीएल की बिक्री अहम
- बीपीसीएल से खजाने में आ सकते हैं **75,000** करोड़ रुपये

# जेपी की बोली आकर्षक बना सकती है सुरक्षा

**भाषा**
नई दिल्ली, 2 दिसंबर

**दिवाला** हो चुकी जेपी इंफ्राटेक के अधिग्रहण की दौड़ में शामिल मुंबई की कंपनी सुरक्षा रियल्टी अपनी बोली का अधिक आकर्षक बना सकती है। कंपनी वित्तीय ऋणदाताओं को अतिरिक्त नकदी और जमीन की पेशकश कर सकती है।

सूत्रों ने सोमवार को बताया कि इसके अलावा सुरक्षा रियल्टी की ओर से घर खरीदारों को आवंटन में देरी के लिए ऊंचे मुआवजे की भी पेशकश की जा सकती है। सार्वजनिक क्षेत्र की एनबीसीसी भी जेपी इंफ्राटेक के लिए बोली लगाने की दौड़ में शामिल है।

एनबीसीसी लिमिटेड भी सक्रिय तरीके से ऋणदाताओं को अधिक जमीन के साथ 20,000 फ्लैटों को पूरा करने की समयसीमा को घटाने की भी पेशकश कर सकती है। ऋणदाताओं की समिति (सीओसी) की 28 नवंबर को हुई बैठक में एनबीसीसी और सुरक्षा रीयल्टी को अपने पिछली बोलियों में संशोधन के बाद अंतिम पेशकश तीन दिसंबर यानी मंगलवार तक देने को कहा है।

सूत्रों ने बताया कि सुरक्षा रियल्टी ऋणदाताओं को किए जाने वाले अग्रिम भुगतान को भी बढ़ा सकती है। पहले उसने ऋणदाताओं को 25 करोड़ रुपये अग्रिम भुगतान की पेशकश की थी। जमीन-ऋण अदला-बदली करार के तहत कंपनी मूल्य के हिसाब से जमीन के टुकड़ों की पेशकश बढ़ा सकती है। फिलहाल उसने 7,800 करोड़ रुपये मूल्य की 1,934 एकड़ जमीन की पेशकश की है। फ्लैट खरीदारों के लिए सुरक्षा रियल्टी विलंब के लिए अधिक जमीन को अलग रखने पर विचार कर रही है। कंपनी ने पहले इसके लिए 100 करोड़ रुपये अलग रखने का प्रस्ताव किया था। कंपनी ने अगले तीन साल में फ्लैटों का निर्माण पूरा करने के लिए 2,000 करोड़ रुपये की कार्यशील पूंजी लाने का प्रस्ताव किया है। कंपनी यमुना एक्सप्रेसवे को अपने पास ही रखना चाहती है। सूत्रों ने रविवार को बताया था कि एनबीसीसी अपनी अंतिम बोली में बिना दावे वाले फ्लैटों और गिरवी रखी जमीन की पेशकश को वापस ले सकती है। इनके बजाय पहले की गई 1,426 एकड़ जमीन की पेशकश के ऊपर और जमीन के टुकड़े देने का प्रस्ताव कर सकती है।

# विनिर्माण गतिविधियां नवंबर में सुधरीं, नौकरियों में कमी

**शुभायन चक्रवर्ती**
नई दिल्ली, 2 दिसंबर

**सोमवार** को जारी एक मासिक वैश्विक सर्वे में कहा गया है कि भारत में विनिर्माण गतिविधियों को गति मिली है, लेकिन फर्में परिचालन लागत में तेजी से कटौती कर रही हैं और 20 महीनों में पहली बार नौकरियों का नुकसान हुआ है।

निक्केई इंडिया मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई नवंबर में बढ़कर 51.2 रहा है, जो अक्टूबर में 50.6 था।

आईएचएस मार्किट इंडिया मैन्यूफैक्चरिंग का परचेजिंग मैनेजर्स सूचकांक (पीएमआई) नवंबर में बढ़ कर 51.2 रहा। सूचकांक का 50 से ऊपर होना उत्पादन में विस्तार का सूचक है, वहीं इससे कम संकुचन दिखाता है।

बहरहाल विनिर्माण क्षेत्र की हालत सुधरी है लेकिन इस क्षेत्र की गतिविधियां इस वर्ष के शुरू के महीनों की तुलना में अभी धीमी बनी हुई हैं। परिणामस्वरूप ज्यादातर फर्मों ने कहा है कि उन्हें छंटनी करनी पड़ी है।

पीएमआई सर्वे में कहा गया है, 'कुछ कंपनियों ने कहा है कि काम का बोझ बढ़ने का प्रबंधन मौजूदा कर्मचारियों से कर लिया गया है, वहीं अन्य ने कहा कि अस्थाई कर्मचारियों का नवीकरण नहीं किया गया है।'

फर्मों ने अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए इनपुट की खरीद की हैं, जबकि पिछले कई महीनों में इसमें गिरावट आई थी। इसके साथ ही खरीद का स्टॉक कम होना लगातार चौथे महीने जारी है। इनपुट खरीद और भंडार में संकुचन की दर कम है।

# नवंबर में यूपीआई से 1.2 अरब ट्रांजैक्शन

**निधि राय**
मुंबई, 2 दिसंबर

**यूनीफाइड** पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) से लेन देन की संख्या नवंबर महीने में 1.22 अरब पहुंच गई, जबकि सितंबर में यह संख्या 1 अरब थी। बहरहाल नवंबर में यूपीआई ट्रांजैक्शन से कुल 1,89,224 करोड़ रुपये का रहा, जो अक्टूबर के 1,91,360 करोड़ रुपये की तुलना में कम है। यह ट्रांजैक्शन अक्टूबर की तुलना में 6.1 प्रतिशत ज्यादा और पिछले साल के समान महीने की तुलना में 132 प्रतिशत ज्यादा है। इस समय यूपीआई से 143 बैंक जुड़े हुए हैं।

बहरहाल बाजार हिस्सेदारों का मानना है कि मूल्य के हिसाब से लेन देन में गिरावट चिंता की बात नहीं है क्योंकि अक्टूबर त्योहारी महीना था। सर्वत्र टेक्नोलॉजिज के संस्थापक और वाइस चेयरमैन मंदर अगासे ने कहा, 'भले ही लेन देन की संख्या बढ़ी है, लेकिन मूल्य के आधार पर देखें तो अक्टूबर की त्योहारी की वजह से इसमें कमी आई है। बहरहाल नए साल और क्रिसमस की वजह से इसमें एक बार फिर तेजी आने की उम्मीद है। इसकी अंतरराष्ट्रीय मौजूदगी बनी है।'

# बैंकों के विलय के लिए टीमें

**देवाशिष महापात्र**
बेंगलूरु, 2 दिसंबर

**केनरा** बैंक और सिंडिकेट बैंक के विलय की प्रक्रिया में करीब 30 समितियां इस समय मानव संसाधन और तकनीक सहित विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े पहलुओं पर विचार कर रही हैं। इस प्रक्रिया के तहत इन बैंकों ने मूल्यांकन और स्वैप रेशियो तय करने के लिए कानूनी और वित्तीय सलाहकारों की भी नियुक्ति की है।

सिंडिकेट बैंक के एमडी और सीईओ मृत्युंजय महापात्र ने बिजनेस स्टैंडर्ड से बातचीत में कहा, 'दोनों बैंकों ने समितियां बनाई हैं, जो विभिन्न क्षेत्रों पर विचार कर रही हैं। वहीं एचआर और ग्राहक सेवा सहित अन्य विषयों पर बी साथ साथ अध्ययन किया जा रहा है, जिससे यह प्रक्रिया आराम से पूरी की जा सके।' उन्होंने कहा कि अगले साल विलय की तिथि के पहले पदोन्नति की प्रक्रिया पूरी करने की भी कवायद कर रहे हैं।

- केनरा व सिंडिकेट बैंक के विलय की गतिविधियां तेज
- मूल्यांकन व स्वैप रेशियो निर्धारित करेंगे कानूनी व वित्तीय सलाहकार
- विलय के बाद बनी इकाई में रह सकते हैं 21 चीफ जनरल मैनेजर
- दोनों बैंक एक ही सीबीएस का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन तकनीक के एकीकरण में लग सकता है वक्त

दोनों बैंकों के अधिकारियों ने कहा कि एचआर एकीकरण प्रक्रिया के तहत समिति सेवा शर्तों, पदोन्नति से जुड़े नियमों, करियर में प्रगति, छुट्टी एवं स्थानांतरण नीति पर विचार कर रही है, जिससे विलय के पहले उचित तालमेल सुनिश्चित हो सके। महापात्र ने कहा, 'मानव संसाधन प्रबंधन व्यवस्था तकनीक के एकीकरण का हिस्सा है, वहीं एचआर मानकों के अन्य पहलुओं पर चर्चा के बाद एक साझा आधार तैयार किया जाएगा।' विलय के बाद बनी इकाई में चीफ जनरल मैनेजरों की संख्या ज्यादा होगी। मौजूदा दिशानिर्देशों के तहत अगर किसी बैंक का कारोबार 10 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा है तो वह प्रत्येक 4 जनरल मैनेजरों पर एक चीफ जनरल मैनेजर नियुक्त कर सकता है। महापात्र ने कहा कि विलय के बाद बनी इकाई में सीजीएम की संख्या 20-21 तक हो सकती है।

# बिजली की खपत और आपूर्ति 5 साल के निचले स्तर पर

**श्रेया जय**
नई दिल्ली, 2 दिसंबर

**भारत** में ऊर्जा की खपत और बिजली आपूर्ति की वृद्धि 5 साल के निचले स्तर पर है। दरअसल जून को छोड़कर इस साल के हर महीने में मांग गिरी है। सरकार ने मौसम और अक्षय ऊर्जा का हवाला देते हुए मांग में कमी को हल्के में लेने की कवायद की है, वहीं देश में बिजली उत्पादन और आपूर्ति की गणित बिगड़ी है। केंद्र सरकार द्वारा राज्यों से बिजली खरीद का भुगतान पहले करने को कहने के बाद खासकर बिजली की मांग ज्यादा घटी है।

जून को छोड़ दें तो चालू कैलेंडर साल के 9 महीनों के दौरान मांग में 2.75 से 14.3 प्रतिशत तक की गिरावट आई है। बिजनेस स्टैंडर्ड ने पिछले 5 साल के बिजली उत्पादन और आपूर्ति के मासिक और सालाना आंकड़े देखे हैं। इससे पता चलता है कि परिकल्पित मांग के मुताबिक राज्य बिजली नहीं खरीद रहे हैं। चालू साल के जून और जुलाई महीने को छोड़ दें तो हर महीने में बिजली की मांग पिछले 5 साल के समान महीने की तुलना में कम रही है।

इस सिलसिले में भेजी गई प्रश्नावली का बिजली मंत्रालय ने कोई जवाब नहीं दिया है।

सितंबर और अक्टूबर महीने में घटी हुई मांग की बड़ी वजह यह हो सकती है कि इस साल मॉनसून की अवधि आगे बढ़ गई थी। लेकिन इस साल जनवरी से ही सरकार के अनुमान की तुलना में वास्तविक मांग कम है। पिछले 5 साल में सभी महीनों के लिए योजनाबद्ध बिजली उत्पादन की तुलना में मांग किसी भी महीने में कभी गिरी नहीं है।

योजनाबद्ध बिजली उत्पादन का अनुमान साल के लिए लगाया जाता है। यह आर्थिक वृद्धि के अनुमान पर निर्भर होता है। वहीं वास्तविक मांग बिजली की आपूर्ति या बिजली कंपनियों द्वारा उत्पादकों से बिजली खरीद से पता चलती है।

इस क्षेत्र के विशेषज्ञों का कहना है कि राज्यों की बिजली खरीद मांग के मुताबिक नहीं है, बल्कि वे उतनी ही बिजली खरीद रहे हैं, जिसका उत्पादन कंपनियों को पहले भुगतान कर सकते हैं। योजना की तुलना में कम खरीद से यह भी संकेत मिलता है कि ग्राहकों को कम आपूर्ति हो रही है और बिजली कटौती हो रही है। भारत में शहर व परिवार के स्तर के बिजली आपूर्ति व कटौती के आंकड़े नहीं हैं। बिजली मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया उर्जामित्र पोर्टल यह काम करता है, जिसमें दिखाया गया है कि देश में औसतन 99 प्रतिशत बिजली उपलब्धता है। इसमें जिलावार कटौती और परिवारों को औसत आपूर्ति के आंकड़े नहीं दिए गए हैं।

केंद्र सरकार ने जून में घोषणा की थी कि बिजली वितरण कंपनियों के लिए बिजली उत्पादकों को बैंकों द्वारा जारी लेटर आफ क्रेडिट (एलसी) के माध्यम से भुगतान करना होगा। उसके अगले महीने में बिजली की मांग 0.33 प्रतिशत गिर गई और यह पिछले साल की तुलना में 6.46 प्रतिशत कम हो गया जब नई सरकार ने अगस्त में कार्यभार संभाला था। अक्टूबर में यह अंतर बढ़कर 14.35 प्रतिशत हो गया।

उपरोक्त उल्लिखित अधिकारी ने कहा कि इसके अलावा कोई भी बैंक उदय योजना में हाथ जलाने के बाद डिस्कॉम के एलसी के वित्तपोषण को तैयार नहीं हुआ।

आर्थिक संकट से जूझ रही राज्यों की बिजली वितरण कंपनियां समस्या में हैं। आर्थिक मंदी की वजह से भुगतान करने वाले उनके औद्योगिक ग्राहक ज्यादा बिजली नहीं खरीद रहे हैं और उन्हें ग्रामीण इलाकों में ज्यादा आपूर्ति करनी पड़ रही है, जहां सब्सिडी पाने वाले उपभोक्ता हैं और हाल ही में वे सौभाग्य योजना के माध्यम से जुड़े हैं।

बिजनेस स्टैंडर्ड ने हाल ही में खबर दी थी कि प्रमुख औद्योगिक राज्यों महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में बिजली की मांग घटी है। इस क्षेत्र के एक अधिकारी ने कहा, 'हमें खबरें मिल रही हैं कि फैक्टरियां एक दिन से एक सप्ताह के लिए बंद हो रही हैं, काम के घंटे कम किए जा रहे हैं। इसकी वजह से बिजली की मांग पर असर पड़ा है। बड़े खरीदार नहीं हैं इसकी वजह से डिस्कॉम का राजस्व प्रभावित हुआ है।'

सरकार द्वारा देश के सभी गांवों (99.9 प्रतिशत) के विद्युतीकरण की घोषणा के एक महीने के भीतर यह झटका लगा है। लेकिन बिजली का दाम बढ़ने के बावजूद इससे वितरण कंपनियों का खर्च बढ़ गया है। अब उनके ऊपर पहले भुगतान की तलवार लटक रही है, ऐसे में डिस्कॉम अपनी बिजली खरीद घटा रही हैं।

**बिजली पर मंदी की मार**

- आपूर्ति के लिए पूर्व भुगतान व्यवस्था प्रभावित कर रही बिजली की मांग
- आर्थिक मंदी की वजह से भुगतान करने वाले उनके औद्योगिक ग्राहक ज्यादा बिजली नहीं खरीद रहे है
- जून को छोड़ दें तो चालू कैलेंडर साल के 9 महीनों के दौरान मांग में 2.75 से 14.3 प्रतिशत तक की गिरावट
- चालू साल के जून और जुलाई महीने को छोड़ दें तो हर महीने में बिजली की मांग पिछले 5 साल के समान महीने की तुलना में कम

## बीएस सूडोकू 3602 | परिणाम संख्या 3601

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 8 | 1 | | | 4 |
| 1 | | 5 | 2 | | | | 8 | |
| | | | | | | 2 | 1 | |
| | 1 | 3 | | | 4 | | | |
| | | 8 | | | | 7 | | |
| | | | 9 | | | 4 | 6 | |
| | 4 | 9 | | | | | | |
| | 8 | | | | 2 | 5 | | 9 |
| 2 | | | 8 | 1 | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 1 | 7 | 4 | 8 | 2 | 6 | 9 |
| 6 | 7 | 2 | 1 | 9 | 3 | 4 | 8 | 5 |
| 9 | 4 | 8 | 2 | 6 | 5 | 1 | 3 | 7 |
| 7 | 2 | 3 | 6 | 5 | 4 | 8 | 9 | 1 |
| 1 | 9 | 4 | 3 | 8 | 7 | 5 | 2 | 6 |
| 8 | 5 | 6 | 9 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 |
| 3 | 8 | 5 | 4 | 1 | 9 | 6 | 7 | 2 |
| 2 | 1 | 9 | 8 | 7 | 6 | 3 | 5 | 4 |
| 4 | 6 | 7 | 5 | 3 | 2 | 9 | 1 | 8 |

**कैसे खेलें?**
हर रो, कॉलम और 3 बाई 3 के बॉक्स में एक से लेकर नौ तक की संख्या भरें।

मध्यम ★★★☆☆

## क्षेत्रीय मंडियों के भाव

उत्तर प्रदेश | राजस्थान | पंजाब

**कानपुर**
गेहूं लूज 2110/2120, जौ 1790/1800, चावल मसूरी 2275/2325, चावल मोटा 2150/2250, सरसों 4300/4325, तिल सफेद 9000/9100, सोया (टीन) 1450/1500, तेल सरसों कच्ची घानी वैट पेड (टीन)1530/1600,
**लखनऊ**
गेहूं दड़ा 2100/2125, गेहूं शरबती 2700/2800, चावल शरबती सेला 3800/3900, स्टीम 4300/4400, लालमती 3300/3400, चावल (सोना) 2950/3000,
**चंदौसी**
(प्रति किलो): मैन्था ऑयल 1440, बोल्ड क्रिस्टल (12 नं.)1530, फ्लैक 1465, डीएमओ 1033, टरपीन लैस बोल्ड 1540
**मुजफ्फरनगर**
गुड़ (40 किलो): लड्डू नया 1030/1100, खुरपा 925/950,चाकू 960/1060, रसकट 800/820, शक्कर 1050/1080, चीनी मिल डिली. (क्विं.) (जीएसटी अतिरिक्त): खतौली 3380, बुंदकी 3300, बुढ़ाना 3360, शामली 3340,
**हापुड़**
गुड़-चीनी: चीनी हाजिर 3550/3650, गुड़ (प्रति 40 किलो) बाल्टी 880/890, तिलहन: सरसों (42 प्रतिशत कंडी.) 4250, खल: सरसों 2250/2350, बिनौला 2600/2700, चना छिलका 1950/2000,
**जयपुर**
अनाज: चावल डीबी 5500/5700, गेहूं (मिल) 2180/2185, मक्की 2070/2075, बाजरा 1840/1850, जौ 1800/1850, ग्वार लूज 3800/3900, ज्वार कैटलफीड 2000/2100, सरसों एक्सपेलर निवाई 8500, कोल्हू कच्ची घानी टोंक 8700,
**श्रीगंगानगर**
गेहूं (देरी) 2000/2050, ग्वार 3900/3950, जौ 2050/2075,
**जोधपुर**
गेहूं 2000/2100, जौ 1750/1800, पोपकोन मक्की 4400/4500, ग्वार डिलीवरी (ऑलपेड) 4100/4150, ग्वारगम 7400/7500, बाजरा (गुजरात) 1900/1950, बाजरा (जयपुर) 1900/1920, चना 4000/4100, काबली चना 4800/6000, मूंग 5900/6000,
**खन्ना**
जीएसटी अतिरिक्त (प्रति क्विं.): राइसब्रान (खाद्य)(प्रति प्याइंट)127, राइसब्रान (अखाद्य) 124, खल सरसों 2080, डीओसी: राइसब्रान बेच सफेद 1250, लाल 1250, कंटीन्यूअस 1300,
**लुधियाना**
दाल-दलहन: राजमां चित्रा 7500/8000, अरहर दाल 7900/8400, उड़द साबुत 7000/8000, उड़द धोया 9200/10000, छिलका 9500/10500, दाल मसूर 5500/5800, चनादाल 5400/5600,
**अमृतसर**
चावल: बासमती (1121 नं.) स्टीम 6400/6500, सेला 5700/5800, शरबती साधारण सेला 3800/3900, शरबती स्टीम 4300/4400,चावल 1509 सेला 5300/5400, धान: शरबती 2100/2150,
**बठिंडा**
रुई (प्रति मन): जे-34 पंजाब नई 3930/3960, हरियाणा 3900/3935, राजस्थान 3850/3930, खल (प्रति क्विं.): बिनौला 2300/2400, सरसों खल 2180/2200,
**फाजिल्का**
गेहूं 2160/2170, सरसों 4275/4325 रुई (प्रति मन): (जे-34) 3950/4000, कपास देशी 4900/5000, कपास नरमा (क्विं.) 5050/5125, बिनौला (टैक्सपेड): खल 2600/2700,
**जालंधर**
गेहूं दड़ा 2130/2140, चावल परमल कच्चा 2450/2500, से ला 2375/2400, मक्की यूपी 2175/2185, बिहार 2325/2335, दाल उड़द छिलका 8800/10200, चना देशी 5100/5200, दाल चना 5275/5360, काबली चना 5000/6000, राजमां चित्रा पुणे 7000/8600, चीन 7400/8000,
**करनाल**
गेहूं दड़ा 2140/2150, बासमती चावल 6500/6600, धान 1121 नं. 2975/3025, पूसा 1509 धान 2700/2800, शरबती धान 2050/2100, सेला (1509 नं.) चावल 5300/5400, स्टीम 6300/6400,
**हिसार**
ग्वार 3850/3900, सरसों 4050/4100, गेहूं 2140/2150,
**जींद**
जीएसटी अतिरिक्त: गेहूं 2100/2150, आटा (प्रति 44 किलो) 1070/1090, मैदा 1175/1190, देशी घी (एक ली/जार) 370/470, रिफाइंड (टीन) 1385/1400,
**भिवानी**
जीएसटी अतिरिक्त: सरसों 4050/4100, खल बिनौला मोटी 2250/2500, बिनौला 2700/3200, सरसों तेल 8700/8750, गेहूं 2125/2175, ग्वार 3800/3850, जौ 1825/1850, नरमा 5100/5150, बाजरा 1800/1900 *एनएनएस*

बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 12 अंक 246

## मौद्रिक नीति की दुविधा

**वित्तीय** बाजार का अनुमान है कि भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) इस सप्ताह छठी बार नीतिगत रीपो दर में कटौती करेगी। चूंकि चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर घटकर 4.5 फीसदी रह गई है, देश की अर्थव्यवस्था की नॉमिनल वृद्धि दर घटकर 6.1 फीसदी हो गई है और सुधार के कोई संकेत नजर नहीं आ रहे हैं तो नीतिगत दरों में कटौती ही उचित प्रतीत होती है। बहरहाल यह निर्णय लेना इतना आसान नहीं होगा। एमपीसी को कई अन्य मसलों पर ध्यान देना होगा। मौजूदा आर्थिक परिदृश्य दुविधा की एक बड़ी वजह है।

पहली बात, खुदरा मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति की दर के बारे में माना जा रहा है कि वह नवंबर में 5 फीसदी का स्तर पार कर गई और विश्लेषकों के अनुसार आने वाले महीनों में भी यह ऊंचे स्तर पर बनी रहेगी।

यह सच है कि शीर्ष मुद्रास्फीति में इजाफा मोटे तौर पर सब्जियों की कीमत में बढ़ोतरी के चलते हुआ और यह महज कुछ दिनों के लिए हो सकती है। कमजोर मूल मुद्रास्फीति भी यही बताती है। जीडीपी अपस्फीतिकारक और थोकमूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति भी निचले स्तर पर है। परंतु केंद्रीय बैंक का लक्ष्य शीर्ष मुद्रास्फीति को लक्षित करना है और यदि वह वास्तविक नीतिगत दरों को ऋणात्मक दायरे में ले जाना चाहती है तो उसे इस बारे में स्पष्ट रूप से बताना होगा।

यदि खाद्य मुद्रास्फीति लंबी अवधि तक ऊंचे स्तर पर रहती है या उसका सामान्यीकरण होता है (वैश्विक वित्तीय संकट के बाद ऐसा हो चुका है) तो इसका असर केंद्रीय बैंक की विश्वसनीयता पर पड़ेगा और मुद्रास्फीति के अनुमानों का प्रबंधन और मुश्किल हो जाएगा।

दूसरा, मौजूदा वित्त वर्ष में केंद्रीय बैंक ने राजकोषीय प्रबंधन में सरकार की बात सुनी है। इसे बदलना होगा। राजस्व की स्थिति को देखते हुए इस बात की संभावना बहुत कम है कि सरकार चालू वित्त वर्ष के लिए तय जीडीपी के 3.3 फीसदी के राजकोषीय लक्ष्य को हासिल कर पाएगी। यदि सरकार कुछ देनदारी सरकारी उपक्रमों की ओर स्थानांतरित भी करती है तो भी समग्र उधारी बढ़ेगी। यह आशंका भी है कि इस वर्ष राज्य भी राजकोषीय मोर्चे पर लक्ष्य से पीछे रह जाएं। इसका असर मौद्रिक नीति पर पड़ेगा। सरकार की राजकोषीय स्थिति भी खराब पारेषण की प्रमुख वजह है। उदाहरण के लिए व्यवस्था में पर्याप्त नकदी होने के बावजूद नीतिगत रीपो दर तथा 10 वर्ष के सरकारी बॉन्ड के प्रतिफल का अंतर 130 आधार अंक के बराबर है। आंशिक तौर पर ऐसा इसलिए है क्योंकि बाजार को यकीन नहीं कि सरकार राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को पूरा कर पाएगी।

तीसरा, दिए गए संदर्भ में एमपीसी अगर यह बताए कि एक और बार दरों में कटौती से वह क्या हासिल करना चाहती है तो बेहतर होगा।

दूसरे शब्दों में कहें तो दी गई परिस्थितियों में मौद्रिक नीति के प्रभाव पर सवाल उठाना जरूरी है। भविष्य में दरों की कटौती की संभावना कम होने के कारण पारेषण आसान नहीं रहेगा। क्या एमपीसी को उस स्थिति में मौद्रिक नीति की सीमाओं का ध्यान रखना चाहिए। बहरहाल, दूसरी ओर अगर फिलहाल दरों में कटौती नहीं की गई तो वित्तीय बाजारों में हड़बड़ी आएगी और बॉन्ड प्रतिफल और बढ़ेगा। ऐसे में एमपीसी के सदस्य संतुलन साधते हुए कटौती कर सकते हैं लेकिन केंद्रीय बैंक को इससे जुड़े जोखिम भी साफ बताने चाहिए और इसकी सीमाओं से भी अवगत कराना चाहिए। दरों में कटौती करने से बात खत्म नहीं हो जाती।

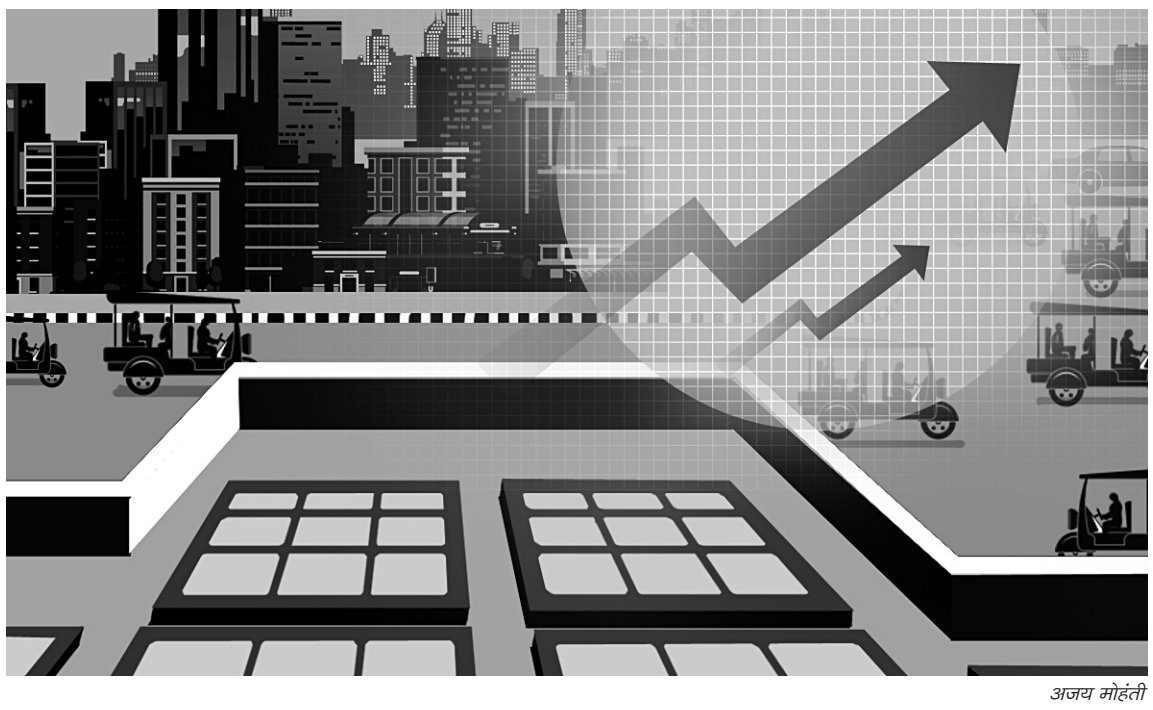

अजय मोहंती

# अर्थव्यवस्था में हरित नीति अपनाने से होगा सुधार

देश की अर्थव्यवस्था को ढांचागत सुधारों के रूप में एक बड़े कदम की आवश्यकता है। इसके साथ ही फिलहाल दूसरी पीढ़ी की हरित नीतियों की भी जरूरत महसूस की जा रही है। विस्तार से बता रहे हैं **अरुणाभ घोष**

क्या हरित अर्थव्यवस्था देश की अर्थव्यवस्था को बचा सकती है? वर्ष 2012-13 की चौथी तिमाही के बाद पहली बार 2019-20 की दूसरी तिमाही में वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 5 फीसदी से नीचे खिसक गई है। सरकारी व्यय, बुनियादी निवेश या उपभोक्ता व्यय से वृद्धि को गति मिल सकती है। परंतु सरकारी व्यय पर राजकोषीय जवाबदेही के नियमों ने अंकुश लगा रखा है। अर्थव्यवस्था को बुनियादी ढांचा क्षेत्र में 1.4 लाख करोड़ रुपये के निवेश की आवश्यकता है, तभी 2024 तक 5 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य हासिल हो सकेगा। परंतु बुनियादी ढांचा क्षेत्र के बकाया भुगतान आदि के कारण निवेश को बरकरार रखना मुश्किल है। उपभोक्ता व्यय 2019-20 की पहली और दूसरी तिमाही के बीच 6.5 फीसदी घटा है।

मौजूदा वृहद आर्थिक दौर में यदि किसी चीज के हरित होने की बात कही जाती है तो यह माना जाता है कि उसके साथ अतिरिक्त लागत जुड़ी होगी। एक दशक पहले जब हरित अर्थव्यवस्था की नीतियां पहली बार प्रभावी हुई थीं तब कई लोग इस पर यकीन करते थे। तब से अब तक भारत ने औद्योगिक क्षेत्र में ऊर्जा किफायत हासिल करने में कामयाबी पाई है, किफायती उपकरण निर्माण की लागत कम की है, हरित इमारतों में इजाफा किया है, जीवाश्म ईंधन सब्सिडी सुधार लागू की, इनकी दरों को न्यूनतम किया और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व क्षमता प्रदर्शित की।

अब अर्थव्यवस्था और हरित अर्थव्यवस्था दोनों की गति में धीमापन आया है। सितंबर में प्रधानमंत्री ने न्यूयार्क में घोषणा की कि नवीकरणीय ऊर्जा की क्षमता को 450 गीगावॉट तक पहुंचाया जाएगा। सन 2022 तक इसे 175 गीगावॉट तक पहुंचाने का लक्ष्य इसलिए हासिल नहीं हो पाएगा क्योंकि अनुबंधों में देरी हुई और विद्युत विक्रय अनुबंधों पर रद्द होने का खतरा मंडराता रहा। केवल अच्छे लक्ष्य तय करने से निवेशक उत्साहित नहीं होते।

ऐसे वक्त में जबकि देश की अर्थव्यवस्था को दूसरी पीढ़ी की हरित नीतियों की आवश्यकता है, देश की अर्थव्यवस्था में ढांचागत सुधारों की आवश्यकता है। दोनों को साथ शुरू करने के लिए चुनिंदा परिस्थितियां आवश्यक हैं। अबाध विकास वाले बाजार, शुरुआती पूंजी निवेश की क्षतिपूर्ति के लिए परिचालन व्यय में कमी, शुद्ध मूल्य वृद्धि के लिए स्वदेशीकरण और सामाजिक और समतामूलक परिस्थितियां। मैं आगामी एक दशक के लिए चार कारक चिह्नित करता हूं।

पहला, वितरित ऊर्जा में मौजूद अवसरों का अब तक लाभ नहीं लिया गया है। रूफटॉप सौर फोटोवॉल्टिक क्षमता करीब 4.3 गीगावॉट है जो 40 गीगावॉट के तय लक्ष्य या उससे अधिक की क्षमता से कम है। वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं के पास थोक क्षमता है और पांच राज्यों महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, गुजरात और कर्नाटक कुल क्षमता का 45 फीसदी पूरा करते हैं। आवासीय उपभोक्ताओं तथा अन्य क्षेत्रों तक विस्तार की काफी गुंजाइश मौजूद है। छत पर नवीकरणीय ऊर्जा उपकरण लगाने से जमीन की बचत भी होती है। परंतु आवासीय उपभोक्ताओं को ऋण के लिए संघर्ष करना पड़ता है। काउंसिल ऑन एनर्जी, एन्वॉयरनमेंट ऐंड वाटर (कीव) ने नया कारोबारी मॉडल विकसित किया है ताकि बिजली वितरण कंपनियां उपभोक्ताओं के साथ सुसंगत बनें और बिजली की लागत में बचत कर सकें। गौरतलब है कि छत पर लगने वाली परियोजना सामान्य सौर परियोजना की तुलना में सात गुना तक अधिक रोजगार तैयार करती है।

दूसरा, गतिशीलता से नई संभावनाएं तैयार होती हैं। रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट और नीति आयोग के मुताबिक सन 2015 से 2030 के बीच देश में वाहनों की तादाद 3.4 से 3.8 गुना तक बढ़ जाएगी। सन 2030 तक वाणिज्यिक कार-जीप और तिपहिया वाहन क्षेत्र में इलेक्ट्रिक व्हीकल का दबदबा हो सकता है। कीव के शोधकर्ताओं का अनुमान है कि यदि सन 2030 तक इलेक्ट्रिक व्हीकल इंजन की लागत के मामले में सामान्य इंजन के समान हो जाता है तो उस समय तक भारत में 2.7 करोड़ इलेक्ट्रिक वाहन होंगे। हमारा अध्ययन बताता है कि सन 2030 में प्रति वाहन कार्बन डाइ ऑक्साइड उत्सर्जन 2 फीसदी से 16 फीसदी कम होगा। एक अन्य सर्वेक्षण में शामिल 37 फीसदी लोगों ने सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल किया और औसतन 1.4 किमी चलकर सार्वजनिक परिवहन की सेवा ली। बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता और सेवाओं की आवृत्ति अहम गतिरोध है। इलेक्ट्रिक वाहन के जरिये हालात में सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है।

यदि स्वदेशीकरण पर ध्यान दिया जाए तो वितरित उत्पादन और गतिशीलता में स्थायित्व अधिक काम आएगा। सन 2030 तक इलेक्ट्रिक वाहनों की 30 फीसदी बिक्री के साथ देश के वाहन क्षेत्र में 5.7 फीसदी मूल्यवर्धन होगा। बशर्ते कि 90 फीसदी पावरट्रेन और बैटरी देश में बनें। घरेलू विनिर्माण के बिना इस क्षेत्र का मूल्यवर्धन 8 फीसदी तक गिरेगा।

बैटरी तकनीक में उल्लेखनीय वृद्धि में संभावनाएं निहित हैं। लिथियम आयन बैटरी की कीमतों में 2010 से अब तक 85 फीसदी गिरावट आई है लेकिन कोरियाई, चीनी और जापानी विनिर्माता बाजार पर दबदबा रखते हैं। इस बीच भारत में इसरो, इंडियन ऑयल और टाटा केमिकल्स कम लागत वाली ली-इयॉन अथवा अल्ट्रा लाइट धातु बैटरियों के निर्माण के साथ प्रयोग कर रहे हैं। ये कंपनियां उत्पादन बढ़ाने के लिए संयुक्त उपक्रम की तलाश में हैं। भविष्य में भंडारण उपकरणों की क्षमता 2018 के 24 गीगावॉट प्रति घंटा से बढ़कर 270 से 365 गीगावॉट प्रति घंटे हो सकती है।

स्वच्छ तकनीक का प्रयोग चौथा कारक है। ऊर्जा की मांग का अहम हिस्सा न केवल वितरित बुनियादी और इलेक्ट्रिक परिवहन के लिए होगा बल्कि कूलिंग की आवश्यकता के लिए भी। सन 2038 तक आवासीय, गतिशीलता और वाणिज्यिक क्षेत्र में प्रशीतन और वातानुकूलन आठ गुना बढ़ेगा। इन तमाम क्षेत्रों में निवेश बढ़ेगा। जब सूरज चमकेगा तब आवासीय ऊर्जा की मांग कम हो सकती है। लोड को इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग या कूलिंग से संतुलित किया जा सकता है।

ग्रामीण क्षेत्रों में वितरित ऊर्जा से चलने वाली किफायती मोटर आय बढ़ाने वाले उपक्रम को ऊर्जावान कर सकती हैं। इस बाजार का अनुमानित आकार 53 अरब डॉलर है। वितरित ऊर्जा फर्म पहले ही 3 लाख प्रत्यक्ष रोजगार तैयार कर चुकी हैं। सौर ऊर्जा आधारित सिंचाई में भी वृद्धि हो रही है। व्यवस्थित बनाने पर यह व्यवहार्य भी हो सकती है। ऐसे में अधिशेष बिजली का इस्तेमाल अन्य ग्रामीण उपभोक्ताओं को जोड़ने के लिए किया जा सकता है। इससे किसानों की आय बढ़ेगी।

वितरित ऊर्जा, स्थायित्व भरी गतिशीलता, स्वदेशीकरण (खासकर बैटरी निर्माण में) और एकीकृत स्वच्छ तकनीक हरित अर्थव्यवस्था के नए वाहक हैं। इनमें से हर कारक नए निवेश को आकर्षित करने वाला है। यह सारी प्रक्रिया मूल्यवर्धन और रोजगार तैयार करने वाली है। बोझ बनने के बजाय हरित सुधार अर्थव्यवस्था को जरूरी बचाव मुहैया कर सकती है।

*(लेखक कौंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरनमेंट ऐंड वाटर के सीईओ हैं)*

## वायु प्रदूषण से निपटने की खातिर कुछ कदम तत्काल उठाना जरूरी

जमीनी हकीकत

सुनीता नारायण

**राष्ट्रीय** राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में वायु प्रदूषण को लेकर जो आपात स्थिति बनी है, उस सिलसिले में यह मेरा तीसरा आलेख है। सबसे पहले मैंने इस विषय पर चर्चा की कि आखिर अब तक उत्सर्जन कम करने के लिए क्या किया गया है। उसके बाद मैंने संकट की प्रकृति के बारे में लिखा कि आखिर क्यों ठंड के दिनों में प्रदूषण इतना विकराल नजर आता है और हमें इससे निपटने के लिए और कदम क्यों उठाने होंगे? इस बार मैं इस विषय पर बात करना चाहती हूं कि आखिर कौन से कदम तत्काल उठाए जाने की जरूरत है और संकट से निपटने के लिए उन्हें किस पैमाने पर उठाना होगा। मैं इस बारे में लिखना चाहती हूं क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया गया तो हम जिस हवा में सांस लेते हैं, उसकी गुणवत्ता को लेकर नाराज तो होंगे लेकिन उस स्थिति में हम स्वच्छ आकाश और साफ फेफड़े नहीं हासिल कर पाएंगे।

लब्बोलुआब यह कि हमें उस पैमाने पर कड़े कदम उठाने की जरूरत है ताकि इतना बदलाव आ सके कि हम निरंतर बढ़ते प्रदूषण को पछाड़ सकें। जब दिल्ली में कंप्रेस्ड नैचुरल गैस (सीएनजी) का इस्तेमाल शुरू हुआ तो एक-दो साल में ही काफी सुधार हुआ। एक लाख से अधिक सार्वजनिक परिवहन वाले वाहनों को सीएनजी के रूप में स्वच्छ ऊर्जा माध्यम पर स्थानांतरित कर दिया गया। ऐसे में हमारे प्रदूषण के आंकड़ों में भी नाटकीय बदलाव आया। हमें आसमान में तारे देखने को मिले। बीते तीन सालों में अहम कदम उठाए गए हैं। दिल्ली में कोयले के इस्तेमाल पर प्रतिबंध से लेकर वाहनों के लिए स्वच्छ ईंधन के इस्तेमाल और ट्रकों से होने वाले प्रदूषण में कमी लाने तक तमाम उपाय किए गए लेकिन ये अपर्याप्त साबित हुए।

प्रश्न यह है कि आगे हम क्या करेंगे? हमें प्रदूषण के प्रमुख स्रोतों के बारे में पता है। यह प्रमुख तौर पर वाहनों, फैक्टरियों, ताप बिजली घरों, डीजल जेनरेटरों, खुले में कचरा जलाने, धूल आदि से फैलता है। फसल अवशेष जलाए जाने के कारण भी महीने भी तक प्रदूषण का प्रकोप बना रहता है। मौसम में बदलाव आते ही यानी हवा बंद होने और नमी बढ़ने पर इसका असर नजर आने लगता है। हमें यह भी पता है कि प्रदूषण को रोकने के लिए उठाए जाने वाले किसी भी कदम का प्रतिरोध भी होता है। वायु प्रदूषण में योगदान करने वाला हर व्यक्ति कहता है कि समस्या हममें नहीं कहीं और है। तो हम क्या करें?

सबसे पहले, हमें स्वच्छ ऊर्जा को अपनाना होगा। इस मसले पर किसी बहस की गुंजाइश नहीं है। हर कोई कहता है कि पेइचिंग ने अपनी हवा साफ कर ली। उन्होंने इसके लिए यही तरीका अपनाया। पेइचिंग के आम परिवारों को और फैक्टरियों से कहा गया कि वे कोयले की जगह स्वच्छ प्राकृतिक गैस का इस्तेमाल करें। हमें यही करने की जरूरत है। केवल दिल्ली नहीं बल्कि आसपास के जितने भी राज्य खराब मौसम और प्रदूषण से परेशान हैं, वहां यह कदम उठाया जाना चाहिए।

अब वक्त आ गया है कि इस क्षेत्र में गैस को लेकर दूसरा बदलाव लाया जाए। पहली बार वाहनों के लिए सीएनजी व्यवस्था लागू की गई थी, अब उद्योगों, बिजली संयंत्रों और घरों में ऐसा करना होगा। तथ्य तो यह है कि गैस की कीमत उस कोयले से अधिक होती है जिसका इस्तेमाल इस क्षेत्र में अत्यधिक प्रदूषणकारी पेट कोक के स्थान पर किया जाता है। उद्योग जगत का कहना है कि यदि वह गैस को अपनाती है तो वह इस क्षेत्र के बाहर के लोगों के साथ प्रतिस्पर्धी नहीं रह पाएगी। उन्हें बंद करना पड़ेगा। तो आखिर काम कैसे चलेगा? या तो गैस कीमत कम करनी होगी या फिर कीमतों से परे इस उद्योग को बंद होने देना होगा। आगे की राह मुश्किल है। कोई आसान विकल्प नहीं है।

दूसरा हल है उद्योग-धंधों और घरों को व्यक्तिगत बिजली उत्पादन (डीजल जेनरेटर) से बिजली पर स्थानांतरित करना। तीसरा उपाय यह सुनिश्चित करना है कि बिजली का उत्पादन यथासंभव स्वच्छ हो। इस क्षेत्र के बड़े हिस्से में (आप आंकड़ों के बारे में चकित होंगे) अभी भी डीजल से चलने वाले जेनरेटरों का इस्तेमाल जमकर होता है। इसके प्रयोग में अपार्टमेंट्स में रहने वाला समृद्ध तबका भी पीछे नहीं है। इस स्थिति में जल्दी बदलाव लाना होगा। यह न तो आसान है और न ही सहज लेकिन स्वच्छ हवा हासिल करने के लिए यह आवश्यक है।

हमें स्वच्छ बिजली संयंत्रों की भी जरूरत होगी। दिल्ली ने पहले ही अपने कोयला आधारित बिजली संयंत्र बंद कर दिए हैं। हमें अब यह सुनिश्चित करना होगा कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के सभी उत्पादन संयंत्र वर्ष 2015 के सख्त उत्सर्जन मानकों का पालन करते हुए गैस का इस्तेमाल करें या बंद कर दिए जाएं। ऐसा करना आसान नहीं है। इसके अलावा वाहनों की बिक्री को भी सीमित करना होगा। उन्हें अधिक स्वच्छ भी बनाना होगा। हमें यह सब पता है लेकिन इस दिशा में कुछ खास नहीं किया जा रहा है।

फसल अवशेष जलाने की समस्या का भी हल तलाश करना होगा। आदर्श हल तो यही होगा कि फसल अवशेष खासकर धान के अवशेष के लिए बाजार मुहैया कराया जाए ताकि किसान उसे जलाने के बजाय बेचें। एक विकल्प यह भी है कि उन्हें ऐसी मशीन मुहैया कराई जाएं जिसकी मदद से वे उन अवशेष को दोबारा मिट्टी में मिला सकें। हल मौजूद हैं केवल उन्हें अपनाने के तरीके तलाश करने हैं। इन सब बातों के अलावा हमें प्रदूषण के स्थानीय स्रोतों पर भी अंकुश लगाना होगा। इसमें कूड़ा जलाने से लेकर कचरा प्रबंधन तक तमाम चीजें शामिल हैं। इसके लिए प्रवर्तन और व्यवस्थित सुधार की आवश्यकता होगी। हमें कूड़े को अलग-अलग करके उसका प्रबंधन करना होगा। यह बात हम सभी जानते हैं।

सबसे अहम बात, हमें इन सभी मोर्चों पर ठोस और वर्ष लंबी कार्य योजना के साथ काम करना होगा। अभी तक प्रदूषण के बढ़ने पर हुए हो हल्ले के बाद हम अगले जाड़े तक शांत हो जाते हैं। ऐसे काम नहीं चलेगा। दिल्ली की हवा को साफ करना सालाना कवायद नहीं बननी चाहिए। इसलिए क्योंकि इसका रिश्ता हमारे स्वास्थ्य और सांस लेने के हमारे अधिकार से है।

## कानाफूसी

### मध्य प्रदेश में फिर से नई जांच

मध्य प्रदेश सरकार का वन विभाग भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हुए पौधरोपण घोटाले को लेकर एक बार फिर नई जांच शुरू करने जा रहा है। जुलाई 2017 में नर्मदा तट पर एक दिन में रिकॉर्ड 7 करोड़ पौधे लगाने का अभियान छेड़ा गया था। मौजूदा कांग्रेस सरकार के वनमंत्री उमंग सिंघार का आरोप है कि तत्कालीन सरकार में शामिल लोगों ने इस दौरान व्यवस्थित तरीके से शासकीय धन की हेराफेरी की। वन विभाग ने जांच के बाद कहा था कि पौधरोपण के आंकड़ों को बहुत अधिक बढ़ाचढ़ाकर पेश किया गया और हकीकत में यह आंकड़ा बहुत कम था। अब सरकार एक नई जांच के द्वारा यह आकलन करने का प्रयास कर रही है कि राज्य की नर्सरियों में इतने पौधे देने की क्षमता थी भी या नहीं।

### बाहर का रास्ता

बहुजन समाज पार्टी (बसपा) ने कुछ वरिष्ठ नेताओं को अनुशासनहीनता और पार्टी हित के खिलाफ काम करने का आरोप लगाकर पार्टी से बाहर निकाल दिया है। इन नेताओं में पूर्व मंत्री और विधायक भी शामिल हैं। इनमें से कई ऐसे भी हैं जिन्होंने मई 2019 के लोकसभा चुनाव और कुछ दिन पहले हुए विधानसभा उपचुनाव में भी शिरकत की थी लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने अपने विश्वसनीय सहयोगी और लखनऊ की मोहनलालगंज लोकसभा सीट से प्रत्याशी रहे सी एल वर्मा को भी बाहर का रास्ता दिखा दिया है। वर्मा को भाजपा के कौशल किशोर के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। दिलचस्प बात है कि वर्मा उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी के भी करीबी हैं। नसीम भी पहले मायावती के सच्चे अनुयायी थे लेकिन बाद में वह कांग्रेस में शामिल हो गए।

## आपका पक्ष

### न्याय व्यवस्था में हो ठोस सुधार

अदालतों में मुकदमों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। यह विभिन्न विसंगतियों को जन्म दे रहा है। राष्ट्रीय अदालत प्रबंधन की रिपोर्ट के मुताबिक बीते तीन दशकों में मुकदमों की संख्या दोगुनी तेजी से बढ़ी है। अगर यही स्थिति बनी रही तो अगले 30 वर्षों में देश की विभिन्न अदालतों में लंबित मुकदमों की संख्या करीब 15 करोड़ तक पहुंच जाएगी। आजादी के बाद से अदालतों और न्यायाधीशों की संख्या आबादी के बढ़ते अनुपात के मुताबिक कभी भी कदमताल नहीं कर पाई है। इस वजह से न्याय के नैसर्गिक सिद्धांत के मुताबिक न्यायपालिका में भी मांग और आपूर्ति के बीच संतुलन कायम नहीं हो सका है। विधि आयोग ने वर्ष 1987 में कहा था कि 10 लाख लोगों पर कम से कम 50 न्यायाधीश होने चाहिए। लेकिन आज भी 10 लाख लोगों पर न्यायाधीशों की संख्या तकरीबन 15 से 20 है। कहते हैं कि दुश्मनों

को भी अस्पताल और कचहरी का मुंह नहीं देखना पड़े। यह इसलिए कहा जाता है क्योंकि दोनों जगह आदमी को तबाह कर देती है और जीतने वाला भी इतने विलंब से न्याय पाता है जो अन्याय के बराबर ही होता है। जमीन के छोटे-छोटे टुकड़े को लेकर पचास-पचास साल मुकदमे चलते हैं। फौजदारी के मामले तो और भी संगीन स्थिति

**एक रिपोर्ट के मुताबिक तीन दशकों में मुकदमों की संख्या दोगुनी तेजी से बढ़ी है**

है। अपराध से ज्यादा सजा लोग फैसला आने के पहले ही काट लेते हैं। यह सब केवल इसलिए होता है कि मुकदमों की सुनवाई और फैसले की गति बहुत धीमी है। तमाम विसंगतियों के बाद भी न्यायालयीन प्रक्रिया के प्रति आम लोगों का बढ़ता विश्वास कुछ इस वजह से भी है कि आम लोगों में विश्वास बहाली के लिए जो कार्य कार्यपालिका को करना चाहिए था वह न्यायालय को करना पड़ा है। पिछले कुछ वर्षों में नेताओं की स्वेच्छाचारिता और गुंडों से उनकी सांठ-गांठ पर चुनाव आयोग और न्यायालय ने मिलकर लगाम कसने की जो सार्थक कोशिश की है, उससे भी आम लोगों का उस पर भरोसा बढ़ा है। अब वक्त आ गया है कि न्याय के लिए न्याय व्यवस्था में ठोस सुधार किया जाए।

*अनु मिश्रा, सीवान*

### उपक्रमों का विनिवेश सही कदम

केंद्र सरकार घाटे में चल रही सार्वजनिक कंपनियों के विनिवेश की प्रक्रिया को तेज करने की तैयारी कर रही है। सरकार इन कंपनियों की हिस्सेदारी बेचकर नकदी जुटाना चाहती है जिससे घाटे में चल रही इन कंपनियों को उबारा जा सके। सरकार ने पहले से ही रणनीति बिक्री के लिए लगभग 35 उपक्रमों की पहचान की है। इनमें एयर इंडिया, बीपीसीएल और प्रमुख इस्पात कंपनी सेल की भद्रावती और दुर्गापुर इकाइयां शामिल हैं। केंद्रीय उपक्रमों में हिंदुस्तान फ्लोरोकार्बन, हिंदुस्तान न्यूजप्रिंट, एचएलएल लाइफकेयर, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स ऐंड इंडिया और सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया तथा आईटीसी इकाइयों में हिस्सेदारी की बिक्री की मंजूरी मिल चुकी है। इन उपक्रमों की बिक्री में बेहतर प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए सभी परिसंपत्तियों की उचित देखभाल सुनिश्चित करने को कहा गया है। सरकार का यह कदम राजस्व घाटे को कम करना है तथा इन कंपनियों को सुचारु रूप से चलाने की दिशा में एक प्रयास है।

*दीप कुमार, महाराजगंज*

**पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिजनेस स्टैंडर्ड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in उस जगह का उल्लेख अवश्य करें, जहां से आप ईमेल कर रहे हैं।**

# घरेलू इस्पात विनिर्माताओं ने बढ़ाए दाम

## अधिकारियों को नहीं लगता कि 2.5 से 3 प्रतिशत का इजाफा लंबे समय तक टिकेगा

**अदिति दिवेकर**
मुंबई, 2 दिसंबर



### वाहन खंड से अनुबंध

- इस्पात के दामों में लगातार दूसरी बार की गई है बढ़ोतरी
- इससे पहले नवंबर में प्रति टन 500 से 1,000 रुपये के बीच इजाफा किया गया था
- इस्पात विनिर्माताओं ने हालिया गिरावट के दौरान वाहन खंड के लिए अर्ध-वार्षिक अनुबंध किए
- इस साल अप्रैल से सितंबर के दौरान देश का इस्पात निर्यात 22 प्रतिशत बढ़ा

मार्जिन पर दबाव से निपटने और मांग में इजाफे की उम्मीद से घरेलू प्राथमिक इस्पात उत्पादकों ने दिसंबर से उत्पादों के दामों में 2.5 से तीन प्रतिशत तक का इजाफा किया है।

जेएसडब्ल्यू स्टील के निदेशक (वाणिज्य एवं विपणन) जयंत आचार्य ने बिजनेस स्टैंडर्ड को बताया कि चूंकि मार्जिन अव्यावहारिक हो गया है इसलिए लागत के मुकाबले इस्पात निर्माण के दामों से विनिर्माताओं का गुजारा करना मुश्किल हो रहा है। इस महीने (दिसंबर) में उत्पाद के दामों में इजाफा करने की यही मुख्य वजह है। यह इजाफा 1 दिसंबर से प्रभावी रहेगा।

दिसंबर में किया जाने वाला यह इजाफा लगातार दूसरे महीने होने वाला इजाफा है। नवंबर में विनिर्माताओं ने लगभग छह महीने के अंतराल के बाद इस्पात उत्पाद के दामों में प्रति टन 500 रुपये से 1,000 रुपये के बीच इजाफा किया था। हालांकि इस्पात विनिर्माताओं को यह उम्मीद है कि बाजार इस दाम वृद्धि को स्वीकार करेगा, लेकिन उद्योग के अन्य अधिकारियों का मानना है कि उपभोक्ता अब भी तैयार नहीं है और इस तरह का लगातार इजाफा लंबे समय तक नहीं टिका रहेगा।

मुंबई के एक कारोबारी ने पहचान उजागर नहीं करने की शर्त पर कहा कि बुनियादी खंड की ओर से मांग बिल्कुल भी नहीं है। साथ ही वाहनों की मांग भी केवल अक्टूबर के त्योहारी महीने में ही अच्छी रही है। कुल मिलाकर इस्पात के लिए अब तक मजबूत मांग का कोई संकेत नहीं है। इस प्रकार के परिदृश्य में लगातार बढ़ रही कीमतों को बनाए रखना मुश्किल रह सकता है।

अक्टूबर 2019 से आठ प्रमुख आधारभूत उद्योगों के सूचकांक में 5.8 प्रतिशत तक की और गिरावट आई है जो आधार वर्ष के रूप में 2011-12 में सूचकांक निर्माण के बाद से इसका सबसे निचला स्तर है। इन आठ खंडों में से इस्पात उद्योग की वृद्धि दर में अक्टूबर के दौरान 1.6 प्रतिशत की गिरावट देखी गई है जो सितंबर में रही 1.5 प्रतिशत की गिरावट से भी ज्यादा है। पिछले साल अक्टूबर के दौरान इस्पात उद्योग में 2.4 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई थी।

इस बीच इस्पात विनिर्माताओं ने इस्पात के दामों में हुई हालिया गिरावट के दौरान वाहन खंड के लिए अर्ध-वार्षिक अनुबंध कर लिए हैं। आचार्य ने कहा कि पहली छमाही से लेकर दूसरी छमाही तक कमी आई है। हालांकि आंकड़े (प्रमुख) अलग-अलग ग्राहकों के आधार पर अलग-अलग रहते हैं इसलिए वह कोई एक आंकड़ा नहीं देना चाहेंगे। जहां एक ओर कुछ भागीदारों ने कहा है कि कीमतों में प्रति टन 6,000 रुपये की कटौती की गई थी, वहीं अन्य भागीदारों का मानना है कि कुल मिलाकर घरेलू इस्पात की कीमतों में गिरावट तेज रही है जो पिछले तीन से चार महीनों के दौरान प्रति टन 8,000 रुपये के आस-पास रही है इसलिए अनुबंध काफी कम कीमत स्तर पर रहने की संभावना है।

शीर्ष घरेलू इस्पात विनिर्माताओं में शुमार जेएसडब्ल्यू स्टील, एस्सार स्टील और टाटा स्टील वाहन क्षेत्र में इस्तेमाल किए जाने वाले चादर उत्पादों में लगी हैं, जबकि सरकारी नियंत्रण वाली भारतीय इस्पात प्राधिकरण (सेल) और जिंदल स्टील ऐंड पावर निर्माण तथा बुनियादी ढांचा खंड की मांग पूरी करती हैं जिसमें लंबे इस्पात उत्पादों का उपयोग किया जाता है।

स्टॉक के संबंध में भी विनिर्माताओं का दृष्टिकोण उद्योग के अन्य अधिकारियों से अलग है। एक तरफ जेएसडब्ल्यू स्टील के आचार्य का कहना है कि स्टॉक के लिहाज से उद्योग आरामदायक स्थिति में है क्योंकि विनिर्माताओं ने अपना उत्पादन कम कर दिया है जिससे स्टॉक कम करने में मदद मिली है। दूसरी तरफ संयुक्त संयंत्र समिति के आंकड़ों के अनुसार पिछले साल के मुकाबले इस साल अप्रैल से सितंबर के दौरान देश का इस्पात निर्यात 22 प्रतिशत बढ़कर तकरीबन 40 लाख टन हो चुका है।

# कागज आयात 30 प्रतिशत बढ़ा

**टीई नरसिम्हन**
चेन्नई, 2 दिसंबर

**कागज** आयात (अखबारी कागज को छोड़कर) में अप्रैल से सितंबर की अवधि के दौरान पिछले साल के मुकाबले मात्रा के हिसाब से करीब 30 प्रतिशत तक और डॉलर के हिसाब से 17.28 प्रतिशत का इजाफा हुआ है। वाणिज्यिक खुफिया एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआईऐंडएस) के आंकड़े बताते हैं कि इस साल अप्रैल से सितंबर के दौरान आयात बढ़कर 70.6 करोड़ डॉलर हो गया है, जबकि एक साल पहले इस अवधि में आयात 60.2 करोड़ डॉलर था। मात्रा के लिहाज से यह 683.5 हजार टन की तुलना में बढ़कर 887.8 हजार टन हो चुका है।

इस वित्त वर्ष के पहले छह महीने के दौरान मूल्य के लिहाज से कुल आयात 19.69 प्रतिशत बढ़कर 4,941 करोड़ रुपये हो गया है, जबकि पिछले साल की इस अवधि में यह 4,128 करोड़ रुपये था। आंकड़े बताते हैं कि मात्रा के लिहाज से चीन और आसियान देशों से आयात में क्रमश: 40 प्रतिशत और 75 प्रतिशत की भारी वृद्धि हुई है।

भारतीय कागज निर्माता संघ (आईपीएमए) ने वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय को पत्र लिखकर इस संबंध में कदम उठाने के लिए कहा है जिसमें मूल सीमा शुल्क में बढ़ोतरी और भारत के मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) की समीक्षा भी शामिल है। इससे तरजीही शुल्क व्यवस्था के तहत काफी कम लागत पर कागज और गत्ते का आयात बढ़ा है और घरेलू उद्योग को नुकसान पहुंचा है।



कागज आयात बढ़ने से घरेलू उद्योग को नुकसान पहुंचा

आईपीएमए के अनुसार पिछले कुछ वर्षों के दौरान भारत-आसियान एफटीए और भारत-कोरिया सीईपीए के अंतर्गत कागज और गत्ते पर मूल सीमा शुल्क में लगातार कमी आई है और वर्तमान में यह शून्य प्रतिशत बैठता है। इसके अलावा एशिया प्रशांत व्यापार समझौते (एपीटीए) के तहत भारत ने चीन (और अन्य देशों) के लिए भी आयात शुल्क छूट बढ़ा दी है तथा कागज के अधिकांश वर्गों पर मूल सीमा शुल्क को मौजूदा 10 प्रतिशत से घटाकर सात प्रतिशत कर दिया है।

आईपीएमए के अध्यक्ष एएस मेहता ने कहा कि भारत ने चालू वित्त वर्ष के पहले छह महीने के दौरान 5,000 करोड़ रुपये का कागज (अखबारी कागज छोड़कर) और गत्ता आयात किया है, जबकि घरेलू उद्योग में मांग पूरी करने के लिए बहुत अधिक क्षमता है। अगर शून्य दरों पर आयात की अनुमति दी जाती है तो घरेलू निवेश सार्थक नहीं होगा।

उन्होंने कहा कि संभवत: भारत दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ने वाला कागज बाजार है। दुर्भाग्य से मौजूदा घरेलू निर्माण क्षमता का कम इस्तेमाल होने से इस मांग वृद्धि को आयात में इजाफे के जरिये पूरा किया जा रहा है।

आईपीएमए का कहना है कि भारत का कागज उद्योग 80 प्रतिशत क्षमता पर चल रहा है जो कागज जैसे लगातार सक्रिय रहने वाले उद्योग और अधिक पूंजी निवेश के लिहाज से कम है। कुछेक कंपनियों के अलावा ज्यादातर क्षेत्र दबाव में है और बढ़ते शुल्क-मुक्त आयात की वजह से वाणिज्यिक रूप से अव्यावहारिक होने की राह पर बढ़ रहा है। कागज उद्योग, विशेष रूप से लकड़ी पर आधारित कागज निर्माताओं से उन लगभग पांच लाख किसानों को मदद मिलती है जो कृषि वानिकी में लगे हुए हैं और कागज मिलों को कच्चे माल की आपूर्ति करते हैं।

आईपीएमए के महासचिव रोहित पंडित ने कहा कि सस्ते आयात से न केवल घरेलू विनिर्माण के हितों को नुकसान पहुंच रहा है, बल्कि बड़ी संख्या में उन किसानों को भी नुकसान पहुंच रहा है जो कृषि वानिकी में लगकर अपनी आमदनी बढ़ाते हैं। उन्होंने वस्तुओं में आसियान-भारत व्यापार समझौते (एआईटीआईजीए) की समीक्षा शुरू करने के फैसले की हालिया घोषणा और आरसेप पर उसके मौजूदा स्वरूप में भारत सरकार द्वारा हस्ताक्षर नहीं करने के फैसले का स्वागत किया है।

आईपीएमए के अनुसार वैश्विक व्यापारिक तनावों के परिणामस्वरूप भारतीय बाजार में बड़ी मात्रा में कागज और गत्ते की डंपिंग होने से देश का लुगदी और कागज उद्योग बहुत कमजोर हो गया है। इसके पीछे मुख्य रूप से इंडोनेशिया और चीन के वे निर्माता हैं जिन्हें बड़ी मात्रा में निर्यात प्रोत्साहन और सस्ते कच्चे माल का लाभ मिलता है।

## अंतरराष्ट्रीय और घरेलू भाव

| As on Dec 2 | International Price | International %Chg# | Domestic Price | Domestic %Chg# |
|---|---|---|---|---|
| METALS ($/tonne) | | | | |
| Aluminium | 1,785.5 | 4.0 | 1,883.9 | -4.6 |
| Copper | 5,854.0 | 4.3 | 6,223.8 | 0.1 |
| Nickel | 13,810.0 | -25.9 | 14,513.0 | -20.3 |
| Lead | 1,947.0 | -3.6 | 2,121.1 | 3.7 |
| Tin | 16,350.0 | -4.7 | 17,303.9 | 0.9 |
| Zinc | 2,312.5 | 3.3 | 2,623.5 | 2.9 |
| Gold ($/ounce) | 1,457.8* | -4.7 | 1,641.8 | -2.0 |
| Silver ($/ounce) | 16.9* | -8.6 | 19.2 | -6.0 |
| ENERGY | | | | |
| Crude Oil ($/bbl) | 61.7* | 4.8 | 64.0 | 10.1 |
| Natural Gas ($/mmBtu) | 2.3* | 2.2 | 2.4 | 1.3 |
| AGRI COMMODITIES ($/tonne) | | | | |
| Wheat | 185.9 | 18.7 | 297.9 | 3.2 |
| Maize | 182.7* | 3.0 | 308.0 | 0.9 |
| Sugar | 345.8* | 13.4 | 483.7 | -1.6 |
| Palm oil | 657.5 | 22.3 | 1,038.2 | 18.8 |
| Rubber | 1,531.0* | 1.7 | 1,828.1 | -6.8 |
| Coffee Robusta | 1,384.0* | 6.1 | 1,876.9 | -10.9 |
| Cotton | 1,419.8 | 9.1 | 1,567.9 | -3.0 |

* As on Dec 02, 19 1800 hrs IST, # Change Over 3 Months, Conversion rate 1 USD = 71.7& 1 Ounce = 31.1032316 grams.

Notes:
1) International metals, Indian basket crude, Malaysia Palm oil, Wheat LIFFE and Coffee Karnataka robusta pertains to previous days price. 2) International metal are LME Spot prices and domestic metal are Mumbai local spot prices except for Steel. 3) International Crude oil is Brent crude and Domestic Crude oil is Indian basket. 4) International Natural gas is Nymex near month future & domestic natural gas is MCX near month futures. 5) International Wheat, White sugar & Coffee Robusta are LIFF E future prices of near month contract. 6) International Maize is MATIF near month future, Rubber is Tokyo-TOCOM near month future and Palm oil is Malaysia FOB spot price. 7) Domestic Wheat & Maize are NCDEX future prices of near month contract, Palm oil & Rubber are NCDEX spot prices. 8) Domestic Coffee is Karnataka robusta and Sugar is M30 Mumbai local spot price. 9) International cotton is Cotton no.2-NYBOT near month future & domestic cotton is MCX Future prices near month tures.

Bloomberg chartMaker — Compiled by BS Research Bureau

## एमसीएक्स

| Name | Tovr (₹ Cr) | OI(000) |
|---|---|---|
| **Agri commodity** | | |
| Cotton | 25.0 | 11957 |
| Oil and Oilseeds | 155.6 | 65556 |
| Spices | 0.9 | 13 |
| **Metal(Nov 29)** | | |
| Metal- non ferrous | 4248.5 | 54951 |
| Metal- precious | 11816.3 | 410 |
| **Oil and gas(Nov 29)** | | |
| Gas | 2882.2 | 48251 |
| Oil | 16896.0 | 2323 |

## एनसीडीईएक्स

| Name | Tovr (₹ Cr) | OI(000) |
|---|---|---|
| **Agri commodity** | | |
| Cotton | 124.7 | 109802 |
| Grains | 228.2 | 101320 |
| Oil and Oilseeds | 677.7 | 489130 |
| Others | 148.5 | 69005 |
| Pulses | 156.3 | 63520 |
| Spices | 76.9 | 29975 |

## एमसीएक्स बढ़ा/घटा

| Name (Maturity) | Close | Day* |
|---|---|---|
| **Gainers (* % Change)** | | |
| Copper (Nov 29) | 447.9 | 4.2 |
| Aluminium Mini (Nov 29) | 136.9 | 3.7 |
| Aluminium (Nov 29) | 136.9 | 3.6 |
| Mentha Oil (Dec 31) | 1315.8 | 3.4 |
| Nickel (Nov 29) | 1069.8 | 3.0 |
| Lead Mini (Nov 29) | 155.4 | 1.6 |
| **Losers (* % Change)** | | |
| Natural Gas (Dec 26) | 167.2 | -5.7 |
| Crude Oil (Dec 18) | 3980.0 | -4.7 |
| Crude Oil Mumbai (Dec 18) | 3983.0 | -4.6 |
| Gold Petal (Nov 29) | 3801.0 | -1.0 |
| Gold Guinea (Nov 29) | 30423.0 | -0.6 |
| Cotton (Dec 31) | 19100.0 | -0.6 |

## एनसीडीईएक्स बढ़ा/घटा

| Name (Maturity) | Close | Day* |
|---|---|---|
| **Gainers (* % Change)** | | |
| Chana-Bikaner (Dec 20) | 4444.0 | 1.3 |
| Soyabean Indore (Dec 20) | 4108.0 | 0.9 |
| Ref Soy Oil-IDR-2016 (Dec 20) | 820.6 | 0.9 |
| Mustard Seed Rape Oil (Dec 20) | 4349.0 | 0.6 |
| Shankar Kapas-Rajkot (Apr 30) | 1072.0 | 0.1 |
| Jeera Unjha (Dec 20) | 16300.0 | 0.1 |
| **Losers (* % Change)** | | |
| CottonSeed Oil-Akola (Dec 20) | 1930.0 | -2.2 |
| GuarGum 5T-Jodhpur (Dec 20) | 7317.0 | -1.8 |
| Moong-Mertacity (Dec 20) | 6500.0 | -1.2 |
| CastorSeed New-Disa (Dec 20) | 4026.0 | -1.2 |
| Coriander-Kota (Dec 20) | 6609.0 | -1.1 |
| Guar Seed 10 (Dec 20) | 4048.0 | -1.0 |

## एमसीएक्स बढ़त/छूट

| Name (Maturity) | Futures | Prem/Dis |
|---|---|---|
| **Premium over spot price** (In %) | | |
| Kapas Surendranagar (Feb 28) | 1043.0 | 5.3 |
| Nickel Mumbai (Nov 29) | 1069.8 | 3.2 |
| Cotton-Rajkot (Dec 31) | 19100.0 | 2.4 |
| Zinc Mumbai (Nov 29) | 189.1 | 1.0 |
| Zinc Mini Mumbai (Nov 29) | 189.1 | 1.0 |
| Silver Ahm (Dec 05) | 44506.0 | 0.8 |
| Silver Micro-Ahemd (Nov 29) | 44506.0 | 0.8 |
| Gold Ahm (Dec 05) | 38031.0 | 0.6 |
| **Discount over spot price** (In %) | | |
| Menthol Oil Chandaus (Dec 31) | 1315.8 | -6.9 |
| Aluminium Mum (Nov 29) | 136.9 | -2.3 |
| Alumini-Mumbai (Nov 29) | 136.9 | -2.3 |
| Copper Mum (Nov 29) | 447.9 | -0.5 |

## एनसीडीईएक्स बढ़त/छूट

| Name (Maturity) | Futures | Prem/Dis |
|---|---|---|
| **Premium over spot price** (In %) | | |
| Paddy-Basmati-Karnal (Dec 20) | 3261.0 | 5.2 |
| Crude Palm Oil Kandl (Dec 31) | 687.0 | 1.0 |
| Soy Bean Indore (Dec 20) | 4108.0 | 0.9 |
| 29 mm Cotton-Rajkot (Dec 20) | 18590.0 | 0.4 |
| Barley Jaipur (Dec 20) | 2133.5 | 0.4 |
| **Discount over spot price** (In %) | | |
| Coriander-Kota (Dec 20) | 6609.0 | -4.7 |
| Turmeric Nizamabad (Dec 20) | 5690.0 | -4.2 |
| Maize-Sangli (Dec 20) | 1903.0 | -3.2 |
| Moong-Merta City (Dec 20) | 6500.0 | -1.8 |
| Guar Gum 5 MT-Jodhpu (Dec 20) | 7317.0 | -1.1 |
| Jeera Unjha (Dec 20) | 16300.0 | -0.9 |

## कल का हाजिर भाव

### औद्योगिक

| Metals | Mumbai | |
|---|---|---|
| Aluminium utensil scrap /kg | 98 | (95) |
| Aluminium ingots /kg | 135 | (135) |
| Brass sheet cutting /kg | 314 | (311) |
| Brass utensil scraps/kg | 294 | (290) |
| Copper heavy scrap /kg | 413 | (409) |
| Copper utensil scraps/kg | 389 | (380) |
| Copper wire bar /kg | 446 | (441) |
| Lead ingots /kg | 152 | (152) |
| Nickel Cathodes /kg | 1040 | (1065) |
| Tin slabs /kg | 1240 | (1235) |
| Zinc slabs /kg | 188 | (188) |

Source:Bombay Metal Exchange

| Cotton | Mumbai | |
|---|---|---|
| Bengal Deshi /Qtl | 10714 | (10714) |
| DCH - 32 /Qtl | 11360 | (11585) |
| Jaydhar /Qtl | 10011 | (10011) |
| Shankar- 6 /Qtl | 11220 | (11304) |

Source:Cotton Association of India

| Oil | Mumbai | |
|---|---|---|
| Castor FSG /10kg | 855 | (880) |
| Castor Comm /10kg | 845 | (870) |
| Ricebran oil/10kg | 760 | (760) |
| Groundnut oil /10kg | 1020 | (1030) |
| Linseed oil /10kg | 845 | (845) |
| Karanji /10kg | 760 | (780) |
| Palm oil /10kg | 760 | (750) |
| Sunflower exp ref /10kg | 830 | (830) |
| Sunflower oil exp /10kg | 790 | (785) |
| Soyabean ref / 10kg | 800 | (795) |

Source:Bombay Commodity Exchange

### सॉफ्ट

| Sugar | Mumbai | |
|---|---|---|
| Mumbai M-30 /Qtl | 3360-3572 | (3360-3572) |

Source:Bombay Sugar Merchants Association

### ऊर्जा

| Crude Brent-$/Barrel | | |
|---|---|---|
| NYSE Crude | 56.54 | (55.17) |
| Brent Crude (UK) | 61.87 | (61.34) |
| Brent Crude (WTI) | 55.17 | (55.17) |
| NYSE Natural Gas-$/Mmbtu | 2.36 | (2.28) |
| Furnace/ 180 Cst &/bbl | 225.12 | (223.27) |
| Naptha spot /Rs/MT | 45170 | (45170) |
| LSHS spot/ M.T. | 36150 | (36150) |
| Furnace Oil spot/ K.L. | 33950 | (33950) |

Source:Petroleum Bazaar.com

### सर्राफा

| Gold | Mumbai | |
|---|---|---|
| Standard (99.50 Purity) /10 gms | 37827 | (37867) |
| Pure (99.90 Purity) /10 gms | 37979 | (38019) |
| Silver.999/ kg | 44200 | (44370) |

Source:India Bullion & Jewellers Association

### @SPOT PRICE(MCX, NCDEX & ICEX)

| Commodity | Unit | PClose | Price (₹.) Close |
|---|---|---|---|
| 29 mm Cotton-Rajkot (N) | 1 B | 18527.00 | 18509.10 |
| Alumini-Mumbai (M) | 1 K | 137.20 | 140.15 |
| Bajra-Delhi (N) | 1 Q | 1890.00 | 1950.00 |
| Barley Jaipur (N) | 1 Q | 2126.45 | 2125.25 |
| Brass-Jamnagar (M) | 1 K | 300.15 | 300.00 |
| Cardamom-Vand. (I) | 1 K | 2960.00 | 2882.00 |
| Castor Seed Disa (N) | 1 Q | 4160.50 | 4007.00 |
| Castor Seed-Kadi (N) | X | 4190.00 | 4190.00 |
| Chana Bikaner (N) | 1 Q | 4244.00 | 4312.75 |
| Chana Delhi (N) | 1 Q | 4400.00 | 4479.55 |
| Chana-Akola (N) | X | 4400.00 | 4375.00 |
| Coriander-Gondal (N) | X | 6775.00 | 6617.00 |
| Coriander-Jaipur (N) | X | 6900.00 | 6875.00 |
| Coriander-Kota (N) | 1 Q | 6960.70 | 6937.15 |
| Cotton Seed Oilck Ak (N) | 1 Q | 2020.30 | 1996.85 |
| Cotton Seed Oilck Ka (N) | 1 Q | 1958.00 | 1932.30 |
| Cotton-Kadi (N) | 1 B | 18504.10 | 18462.30 |
| CPO-Kandla (M) | 10 K | 672.60 | 680.60 |
| Crude Palm Oil Kandl (N) | 10 K | 682.40 | 680.20 |
| Diamond 0.3 - Surat (I) | 1 CT | 883.55 | 881.85 |
| Diamond 0.5-Surat (I) | 1 CT | 1541.90 | 1541.80 |
| Diamond 1-Surat (I) | 1 CT | 3474.95 | 3472.20 |
| Gold Ahm (M) | 10 G | 37876.00 | 37795.00 |
| Gold Guinea-Ahmedaba (M) | 8 G | 30423.00 | 30358.00 |
| Gold Petal-Mumbai (M) | 1 G | 3801.00 | 3794.00 |
| Guar Gum 5 MT-Jodhpu (N) | X | 7544.50 | 7400.00 |
| Guar Seed 10 MT-Jodh (N) | 1 Q | 4050.25 | 3999.10 |
| Guarseed-Jodhpur (I) | 1 Q | 4050.00 | 4000.00 |
| Gur Muzaffar Nagar (N) | 40 K | 1017.85 | 1017.85 |
| Isabgulseed-Unjha (I) | 1 K | 93.90 | 93.25 |
| Jeera Jodhpur-Jodhpu (N) | X | 17000.00 | 17100.00 |
| Jeera Unjha (N) | 1 Q | 16516.65 | 16455.25 |
| Kapas Kadi-Kadi (N) | X | 1002.55 | 998.40 |
| Kapas-Rajkot (N) | X | 990.45 | 991.00 |
| Lead Mum (M) | 1 K | 155.25 | 155.25 |
| Maize Kharif-Nizamab (N) | X | 1872.50 | 1897.50 |
| Maize Rabi-Gulabbagh (N) | 1 | 2200.00 | 2245.15 |
| Maize-Erode (N) | X | 1950.00 | 2066.65 |
| Maize-Feed/Ind-Delhi (N) | 1 Q | 2117.50 | 2110.00 |
| Maize-Sangli (N) | X | 1896.35 | 1965.00 |
| Moong-Merta City (N) | 1 Q | 6557.80 | 6622.50 |
| Mustardseed Alwar (N) | 20 K | 4488.50 | 4514.25 |
| Nickel Mumbai (M) | 1 K | 1051.90 | 1037.10 |
| Paddy-Basmati-Karnal (N) | X | 3250.00 | 3100.00 |
| Paddy-Basmati-Karnal (I) | 1 Q | 3270.00 | 3140.00 |
| Pepper-Ernakulam (I) | 1 K | 350.60 | 349.40 |
| Pepper-Kochi (N) | 1 Q | 35120.00 | 34850.00 |
| Rape mustards-Patan (I) | 20 K | 782.00 | 782.00 |
| Rapeseed Must.Seed (N) | X | 2086.90 | 2095.25 |
| RBD Palm Olein Kakin (N) | 10 K | 736.90 | 744.00 |
| Ref Soya Oil Indore (N) | 10 K | 810.50 | 815.25 |
| Ref Soya Oil Mum (N) | 10 K | 801.00 | 803.15 |
| Ref Soya Oil Nagpur (N) | 10 K | 814.00 | 815.00 |
| Rubber-Kochi (N) | 1 Q | 13000.00 | 13100.00 |
| Rubber-Kochi/Ernak. (I) | 1 Q | 13050.00 | 13100.00 |
| Silver M-Ahemdabad (M) | 1 K | 44303.00 | 44132.00 |
| Soy Bean Indore (N) | 1 Q | 4057.00 | 4070.00 |
| Soy Bean Kota (N) | 1 Q | 4040.00 | 3989.50 |
| Soy Bean Nagpur (N) | 1 Q | 4022.35 | 4040.00 |
| Soy Bean-Akola (N) | X | 4095.00 | 4070.00 |
| Soymeal Indore (N) | 1 T | 33500.00 | 33500.00 |
| Soyoil-Indore (I) | 10 K | 810.20 | 808.10 |
| Steel Long-Ghaziabad (I) | 1 T | 28000.00 | 27930.00 |
| Steel Long-MGG (I) | 1 T | 29200.00 | 29010.00 |
| Steel Long-Raipur (I) | 1 T | 26070.00 | 26010.00 |
| Sugar M Delhi (N) | 1 Q | 3345.00 | 3295.00 |
| Sugar M Grade-Kanpur (N) | 1 Q | 3413.65 | 3390.30 |
| Sugar M Grade-Kolhap (N) | 1 Q | 3298.75 | 3271.65 |
| Sugar M Kolkatta (N) | 1 Q | 3500.00 | 3457.15 |
| Sugar M Muzaff (N) | 1 Q | 3337.50 | 3305.65 |
| Sugar S-Kolhapur (N) | 1 Q | 3134.15 | 3123.75 |
| Turmeric Nizamabad (N) | 1 Q | 5968.75 | 5938.65 |
| Wheat Delhi (N) | 1 Q | 2269.15 | 2252.50 |
| Wheat Kota (N) | 1 Q | 2127.50 | 2140.00 |
| Wheat New Indore (N) | 1 Q | 2190.00 | 2192.50 |
| Wheat New Kanpur (N) | 1 Q | 2078.75 | 2073.75 |
| Wheat New-Rajkot (N) | 1 Q | 2165.00 | 2195.00 |
| Yellow Peas Mum (N) | 1 Q | 4625.00 | 4655.40 |
| Zinc Mumbai (M) | 1 K | 188.95 | 187.25 |

* as on Nov 29, 19

(M) MCX ,(N) NCDEX & (I) ICEX Spot prices

## जिंस वायदा




**DAY SESSION**

### दिवस सत्र (सोमवार)

### कृषि जिंस

**Cotton**

| Maturity | Open, High Low Close | Qty | Trds | OI |
|---|---|---|---|---|
| **Cotton MCX(1 B)** | | | | |
| Dec 31 | 19150, 19210, 19100, 19100 | 1956 | 301 | 9209 |
| Jan 31 | 19320, 19370, 19270, 19290 | 247 | 51 | 2100 |
| **CottonSeed Oil-Akola NCDEX(1 Q)** | | | | |
| Dec 20 | 1982, 2005, 1915, 1930 | 26230 | 1907 | 41280 |
| Jan 20 | 2002, 2008, 1940, 1956 | 29500 | 2217 | 43350 |
| Feb 20 | 2013, 2020, 1963, 1982 | 3170 | 289 | 19020 |
| Mar 20 | 2011, 2020, 1994, 2004 | 270 | 26 | 2270 |
| **Kapas MCX(20 K)** | | | | |
| Apr 30 | 1071, 1074, 1070, 1072.5 | 28 | 7 | 584 |
| **Shankar Kapas-Rajkot NCDEX(20 Kg)** | | | | |
| Apr 30 | 1071, 1077, 1069.5, 1072 | 419 | 280 | 3882 |

**Grains**

| Maturity | Open, High Low Close | Qty | Trds | OI |
|---|---|---|---|---|
| **Guar Seed 10 NCDEX(1 Qtl)** | | | | |
| Dec 20 | 4100, 4100, 3988, 4048 | 25805 | 3362 | 45455 |
| Jan 20 | 4086, 4112, 4028, 4082 | 30160 | 3815 | 52280 |
| Feb 20 | 4130, 4142, 4074, 4134 | 200 | 40 | 825 |

**Oil and Oilseeds**

| Maturity | Open, High Low Close | Qty | Trds | OI |
|---|---|---|---|---|
| **CastorSeed New-Disa NCDEX(1 Qtl)** | | | | |
| Dec 20 | 4048, 4056, 3956, 4026 | 11810 | 1370 | 33285 |
| Jan 20 | 4092, 4098, 4002, 4070 | 10530 | 1293 | 20765 |
| Feb 20 | 4010, 4070, 3980, 3998 | 195 | 27 | 3750 |
| Mar 20 | 4020, 4048, 3962, 4012 | 295 | 35 | 2820 |
| **Crude Palm Oil MCX(10 K)** | | | | |
| Dec 31 | 676, 683.9, 672.9, 682.9 | 12450 | 862 | 53830 |
| Jan 31 | 675, 683.8, 674.4, 683.2 | 2930 | 238 | 11230 |
| Feb 28 | 678, 686.5, 677.5, 685.3 | 220 | 20 | 200 |
| **Mentha Oil MCX(1 K)** | | | | |
| Dec 31 | 1278.8, 1320, 1278.8, 1315.8 | 354.96 | 796 | 283.32 |
| Jan 31 | 1293.1, 1325.6, 1293.1, 1323.9 | 27 | 63 | 12.96 |
| **Mustard Seed Rape Oil NCDEX(1 Q)** | | | | |
| Dec 20 | 4335, 4355, 4315, 4349 | 9690 | 745 | 28280 |
| Jan 20 | 4360, 4392, 4348, 4386 | 4910 | 412 | 5530 |
| Feb 20 | 4365, 4375, 4365, 4375 | 110 | 8 | 110 |
| Apr 20 | 4270, 4274, 4270, 4270 | 100 | 8 | 1110 |
| May 20 | 4300, 4300, 4300, 4300 | 10 | 1 | 30 |
| **Ref Soy Oil-IDR-2016 NCDEX(10 Kg)** | | | | |
| Dec 20 | 813, 822, 810.2, 820.6 | 12720 | 1122 | 30920 |
| Jan 20 | 818, 825.8, 814.6, 824.4 | 13080 | 957 | 43475 |
| Feb 20 | 816.2, 825, 816.2, 823.8 | 1035 | 107 | 6695 |
| Mar 20 | 820, 824.8, 818, 822 | 25 | 5 | 25 |
| **Soyabean Indore NCDEX(1 Q)** | | | | |
| Dec 20 | 4080, 4120, 4074, 4108 | 24545 | 2888 | 59880 |
| Jan 20 | 4120, 4150, 4100, 4138 | 33040 | 3658 | 147365 |
| Feb 20 | 4138, 4172, 4126, 4156 | 11685 | 1364 | 83020 |
| Mar 20 | 4150, 4198, 4150, 4178 | 4020 | 503 | 21880 |

**Others**

| Maturity | Open, High Low Close | Qty | Trds | OI |
|---|---|---|---|---|
| **GuarGum 5T-Jodhpur NCDEX(1 Qtl)** | | | | |
| Dec 20 | 7398, 7558, 7230, 7317 | 9280 | 1200 | 20790 |
| Jan 20 | 7501, 7550, 7334, 7422 | 10605 | 1535 | 47820 |
| Feb 20 | 7500, 7560, 7445, 7547 | 230 | 32 | 345 |

**Pulses**

| Maturity | Open, High Low Close | Qty | Trds | OI |
|---|---|---|---|---|
| **Chana-Bikaner NCDEX(1 Qtl)** | | | | |
| Dec 20 | 4370, 4486, 4360, 4444 | 15890 | 1220 | 30440 |
| Jan 20 | 4375, 4492, 4375, 4459 | 17510 | 1303 | 30720 |
| Mar 20 | 4354, 4439, 4340, 4376 | 1720 | 141 | 2050 |
| Apr 20 | 4263, 4345, 4263, 4345 | 120 | 12 | 210 |
| **Moong-Mertacity NCDEX(1 Qtl)** | | | | |
| Dec 20 | 6420, 6500, 6400, 6500 | 125 | 5 | 50 |

**Spices**

| Maturity | Open, High Low Close | Qty | Trds | OI |
|---|---|---|---|---|
| **Cardamom MCX(1 K)** | | | | |
| Dec 13 | 2890, 2890, 2833.5, 2868.1 | 0.6 | 6 | 3 |
| Jan 15 | 2825.7, 2870, 2790, 2805.5 | 2.5 | 24 | 8.2 |
| **Coriander-Kota NCDEX(1 Q)** | | | | |
| Dec 20 | 6695, 6698, 6485, 6609 | 2850 | 228 | 7190 |
| Jan 20 | 6651, 6651, 6451, 6572 | 1630 | 117 | 4730 |
| Apr 20 | 6980, 6980, 6870, 6915 | 220 | 18 | 2360 |
| **Jeera Unjha NCDEX(1 Q)** | | | | |
| Dec 20 | 16335, 16375, 16180, 16300 | 1779 | 260 | 2466 |
| Jan 20 | 16110, 16215, 16060, 16165 | 399 | 92 | 1176 |
| Mar 20 | 15800, 15875, 15800, 15875 | 15 | 4 | 213 |
| **Turmeric Nizamabad NCDEX(1 Q)** | | | | |
| Dec 20 | 5740, 5740, 5638, 5690 | 1085 | 204 | 8690 |
| Mar 20 | 6032, 6090, 6002, 6066 | 520 | 104 | 1870 |
| Apr 20 | 6060, 6108, 6050, 6098 | 170 | 33 | 1275 |

### धातु

**Metal- non ferrous**

| Maturity | Open, High Low Close | Qty | Trds | OI |
|---|---|---|---|---|
| **Aluminium MCX(1 K)** | | | | |
| Dec 31 | 133.7, 134.2, 133.1, 133.35 | 5200 | 840 | 8720 |
| **Aluminium Mini MCX(1 K)** | | | | |
| Dec 31 | 133.55, 134.1, 133.1, 133.4 | 2286 | 1699 | 3259 |
| Jan 31 | 134.7, 134.95, 134.1, 134.2 | 202 | 119 | 203 |
| **Copper MCX(1 K)** | | | | |
| Dec 31 | 433.5, 435, 433.15, 433.55 | 13305 | 4236 | 15400 |
| Jan 31 | 439.25, 439.9, 438.1, 438.35 | 207.5 | 82 | 757.5 |
| **Lead MCX(1 K)** | | | | |
| Dec 31 | 153.7, 153.95, 152.7, 152.85 | 8850 | 1450 | 7555 |
| **Lead Mini MCX(1 K)** | | | | |
| Dec 31 | 153.7, 153.95, 152.8, 152.95 | 3953 | 3116 | 3379 |
| Jan 31 | 154, 154.1, 153.15, 153.3 | 43 | 38 | 56 |
| **Nickel MCX(1 K)** | | | | |
| Dec 31 | 1010.3, 1012.8, 998.3, 1007.2 | 9325.5 | 5566 | 2799 |
| Jan 31 | 1007, 1007.6, 995.7, 1005.7 | 102 | 68 | 73.5 |
| Feb 28 | 982.8, 1012.4, 982.8, 997.6 | 3 | 2 | - |
| **Zinc MCX(1 K)** | | | | |
| Dec 31 | 185.6, 185.6, 184.1, 184.5 | 18020 | 2949 | 20115 |
| **Zinc Mini MCX(1 K)** | | | | |
| Dec 31 | 185.15, 185.55, 184.35, 184.7 | 6089 | 4564 | 6226 |
| Jan 31 | 185.7, 185.7, 184.5, 184.65 | 141 | 133 | 368 |
| Feb 28 | 185, 185, 185, 185 | 1 | 1 | 3 |

ELECTRICITY TRADING AT IEX
Market price in ~/MWh




**Metal- precious**

| Maturity | Open, High Low Close | Qty | Trds | OI |
|---|---|---|---|---|
| **Gold MCX(10 G)** | | | | |
| Dec 05 | 37717, 37970, 37100, 37796 | 0.42 | 312 | 0.17 |
| Feb 05 | 37928, 37929, 37770, 37814 | 5.5 | 4507 | 16.65 |
| Apr 03 | 37873, 37943, 37829, 37841 | 0.18 | 147 | 1.7 |
| **Gold Guinea MCX(8 G)** | | | | |
| Dec 31 | 30530, 30548, 30439, 30490 | 0 | 162 | 0 |
| Jan 31 | 30500, 30509, 30470, 30489 | 0 | 6 | 0 |
| **Gold Mini MCX(10 G)** | | | | |
| Dec 05 | 38240, 38240, 37715, 37855 | 0.06 | 138 | 0.08 |
| Jan 03 | 37951, 37966, 37827, 37878 | 0.5 | 4182 | 0.9 |
| Feb 05 | 37905, 37927, 37792, 37835 | 0.11 | 936 | 0.13 |
| **Gold Petal MCX(1 Gm)** | | | | |
| Dec 31 | 3871, 3871, 3859, 3862 | 0 | 526 | 0.01 |
| Jan 31 | 3851, 3860, 3850, 3850 | 0 | 102 | 0 |
| Mar 31 | 3900, 3900, 3900, 3900 | 0 | 1 | 0 |
| **Silver MCX(1 K)** | | | | |
| Dec 05 | 44290, 44416, 44077, 44135 | 9.21 | 232 | 12.42 |
| Mar 05 | 44949, 44949, 44549, 44614 | 189.99 | 5089 | 349.86 |
| May 05 | 45383, 45383, 45101, 45125 | 0.69 | 22 | 0.6 |
| **Silver Micro MCX(1 K)** | | | | |
| Feb 28 | 44963, 44963, 44580, 44642 | 19.34 | 12408 | 27.13 |
| Apr 30 | 45411, 45411, 45119, 45173 | 0.58 | 487 | 0.73 |
| **Silver Mini MCX(1 K)** | | | | |
| Feb 28 | 44945, 44945, 44557, 44637 | 57.2 | 9022 | 51.54 |
| Apr 30 | 45414, 45414, 45119, 45163 | 0.57 | 108 | 0.39 |

### तेल एवं गैस

**Gas**

| Maturity | Open, High Low Close | Qty | Trds | OI |
|---|---|---|---|---|
| **Natural Gas MCX(1 MB)** | | | | |
| Dec 26 | 169.2, 170.6, 168.2, 169.2 | 53400mb | 23707 | 40839mb |
| Jan 28 | 167.5, 169.7, 167.4, 168.5 | 4765mb | 2161 | 8833mb |
| Feb 25 | 164.2, 165.4, 163.3, 164.5 | 651mb | 402 | 1249mb |

**Oil**

| Maturity | Open, High Low Close | Qty | Trds | OI |
|---|---|---|---|---|
| **Crude Oil MCX(1 BL)** | | | | |
| Dec 18 | 4000, 4067, 4000, 4046 | 9865bl | 46978 | 2539bl |
| Jan 17 | 4039, 4077, 4023, 4057 | 181bl | 1337 | 135bl |
| **Crude Oil Mumbai MCX(1 Bl)** | | | | |
| Dec 18 | 3971, 4066, 3971, 4046 | 1878bl | 73919 | 552bl |

### सायं सत्र (शुक्रवार)

### कृषि जिंस

**Cotton**

| Maturity | Open, High Low Close | Qty | Trds | OI |
|---|---|---|---|---|
| **Cotton MCX(1 B)** | | | | |
| Dec 31 | 19270, 19290, 19130, 19150 | 2793 | 401 | 9337 |
| Jan 31 | 19390, 19420, 19320, 19340 | 102 | 18 | 2160 |
| Mar 31 | 19990, 19990, 19990, 19990 | 04 | 1 | 17 |
| **Kapas MCX(20 K)** | | | | |
| Apr 30 | 1070, 1074, 1069, 1070.5 | 80 | 20 | 576 |
| **Shankar Kapas-Rajkot NCDEX(20 Kg)** | | | | |
| Apr 30 | 1070, 1074, 1066, 1071 | 741 | 400 | 3807 |

**Oil and Oilseeds**

| Maturity | Open, High Low Close | Qty | Trds | OI |
|---|---|---|---|---|
| **Crude Palm Oil MCX(10 K)** | | | | |
| Dec 31 | 672.8, 682, 671.5, 680 | 31510 | 1787 | 54320 |
| Jan 31 | 671.5, 683.3, 670.2, 681.2 | 4990 | 305 | 11140 |
| **Ref Soy Oil-IDR-2016 NCDEX(10 Kg)** | | | | |
| Dec 20 | 810.8, 816.65, 810.15, 814.4 | 21670 | 1453 | 36260 |
| Jan 20 | 815, 819, 814, 817.8 | 18950 | 1035 | 39380 |
| Feb 20 | 819.15, 819.15, 814, 818.4 | 4200 | 207 | 6360 |

### धातु

**Metal- non ferrous**

| Maturity | Open, High Low Close | Qty | Trds | OI |
|---|---|---|---|---|
| **Aluminium MCX(1 K)** | | | | |
| Dec 31 | 133.35, 133.75, 132.95, 133.55 | 11170 | 1659 | 7815 |
| **Aluminium Mini MCX(1 K)** | | | | |
| Dec 31 | 133.5, 133.75, 132.9, 133.5 | 3385 | 2765 | 3156 |
| Jan 31 | 134.65, 134.8, 134.2, 134.6 | 73 | 66 | 121 |
| **Copper MCX(1 K)** | | | | |
| Dec 31 | 433.7, 435, 432, 432.6 | 20947.5 | 6995 | 13470 |
| Jan 31 | 439.25, 439.8, 437.05, 437.75 | 292.5 | 115 | 677.5 |
| **Lead MCX(1 K)** | | | | |
| Dec 31 | 153.7, 154.65, 153.35, 153.6 | 16775 | 2638 | 5415 |
| **Lead Mini MCX(1 K)** | | | | |
| Dec 31 | 153.8, 154.65, 153.45, 153.7 | 6641 | 5150 | 2187 |
| Jan 31 | 154.1, 154.6, 153.8, 154 | 48 | 48 | 43 |
| **Nickel MCX(1 K)** | | | | |
| Dec 31 | 1025, 1029.6, 1001.1, 1005.5 | 18394.5 | 10929 | 1993.5 |
| Jan 31 | 1025.4, 1025.5, 1000.6, 1002.6 | 237 | 153 | 63 |
| **Zinc MCX(1 K)** | | | | |
| Dec 31 | 185.35, 185.85, 184.25, 185.05 | 33710 | 5527 | 13635 |
| **Zinc Mini MCX(1 K)** | | | | |
| Dec 31 | 185.5, 185.95, 184.2, 185.15 | 12572 | 9461 | 4445 |
| Jan 31 | 185.55, 185.85, 184.85, 185.5 | 140 | 115 | 323 |
| Feb 28 | 185.5, 185.5, 185, 185.25 | 2 | 2 | 2 |

**Metal- precious**

| Maturity | Open, High Low Close | Qty | Trds | OI |
|---|---|---|---|---|
| **Gold MCX(10 G)** | | | | |
| Dec 05 | 37782, 38114, 37693, 38031 | 5.66 | 3741 | 0.6 |
| Feb 05 | 37809, 38074, 37712, 38004 | 12.06 | 10248 | 16.26 |
| Apr 03 | 37840, 38099, 37785, 38029 | 1.06 | 932 | 1.62 |
| **Gold Guinea MCX(8 G)** | | | | |
| Dec 31 | 30492, 30600, 30440, 30587 | 0 | 427 | 0 |
| Jan 31 | 30411, 30589, 30411, 30534 | 0 | 21 | 0 |
| Feb 28 | 30689, 30800, 30550, 30682 | 0 | 4 | 0 |
| **Gold Mini MCX(10 G)** | | | | |
| Dec 05 | 37770, 38070, 37711, 37961 | 0.43 | 2601 | 0.09 |
| Jan 03 | 37818, 38082, 37751, 38024 | 1.38 | 11129 | 0.8 |
| Feb 05 | 37816, 38071, 37741, 38015 | 0.19 | 1684 | 0.11 |
| **Gold Petal MCX(1 Gm)** | | | | |
| Dec 31 | 3858, 3874, 3853, 3872 | 0 | 1503 | 0.01 |
| Jan 31 | 3847, 3862, 3843, 3861 | 0 | 272 | 0 |
| **Silver MCX(1 K)** | | | | |
| Dec 05 | 44225, 44622, 44155, 44506 | 205.23 | 4784 | 15.45 |
| Mar 05 | 44867, 45164, 44635, 45055 | 455.55 | 12388 | 304.41 |
| May 05 | 45380, 45513, 45314, 45436 | 0.24 | 8 | 0.27 |
| **Silver Micro MCX(1 K)** | | | | |
| Nov 29 | 43990, 44640, 43990, 44506 | 31.65 | 19226 | 4.47 |
| Feb 28 | 44820, 45155, 44676, 45086 | 28.51 | 17313 | 20.44 |
| Apr 30 | 45550, 45700, 45216, 45606 | 0.87 | 708 | 0.58 |
| **Silver Mini MCX(1 K)** | | | | |
| Nov 29 | 44254, 44680, 44152, 44506 | 73.33 | 10728 | 6.28 |
| Feb 28 | 44816, 45149, 44669, 45078 | 86.85 | 13844 | 37.93 |
| Apr 30 | 45470, 45690, 45250, 45627 | 0.73 | 138 | 0.31 |

### तेल एवं गैस

**Gas**

| Maturity | Open, High Low Close | Qty | Trds | OI |
|---|---|---|---|---|
| **Natural Gas MCX(1 MB)** | | | | |
| Dec 26 | 177.2, 178.5, 166.7, 167.2 | 154704mb | 69904 | 38203mb |
| Jan 28 | 176.5, 177.5, 165.8, 166.6 | 11375mb | 5942 | 8940mb |
| Feb 25 | 171.8, 172.7, 162.4, 163.1 | 1095mb | 766 | 1109mb |

**Oil**

| Maturity | Open, High Low Close | Qty | Trds | OI |
|---|---|---|---|---|
| **Crude Oil MCX(1 BL)** | | | | |
| Dec 18 | 4173, 4180, 3958, 3980 | 33581bl | 153595 | 1753bl |
| Jan 17 | 4170, 4187, 3974, 3988 | 743bl | 5260 | 149bl |
| Feb 19 | 4152, 4152, 4050, 4101 | 0bl | 2 | 0bl |
| **Crude Oil Mumbai MCX(1 Bl)** | | | | |
| Dec 18 | 4180, 4180, 3959, 3983 | 7095bl | 256052 | 420bl |

*g-grams, k-kilograms, q-quintals, t-tonnes, b-bales,bl-barels,mb-mmBTU,m-Mnd; Quantity & Open interest in tonnes except for crude oil and natural gas; For Gas is '000 mmBTU & for crudeoil in '000 barrel; Market price in ₹.*

# महाराष्ट्र में अभी थमा नहीं राजनीतिक भूचाल

सुशील मिश्र

**महाराष्ट्र** की सत्ता हाथ से निकलने के बाद भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) राज्य में एक आक्रामक विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए स्वयं को तैयार करने में शिद्दत से जुटी थी। लेकिन पिछले कुछ दिनों के घटनाक्रम ने सत्ताधारी दलों को ही भाजपा पर हावी होने का मौका थमा दिया है। दूसरी तरफ भाजपा की पंकजा मुंडे के तेवर ने भी मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। भाजपा नेता अनंत हेगड़े के बयान के बाद राज्य में राजनीति गर्म हो गई है। हेगड़े ने कहा था कि देवेंद्र फडणवीस ने बतौर मुख्यमंत्री 15 घंटों में 40,000 करोड़ रुपये केंद्र को वापस कर दिए। हेगड़े ने यह भी कहा था कि शिवसेना गठबंधन इस रकम का बेजा इस्तेमाल कर सकता था, जिसके मद्देनजर फडणवीस ने यह कदम उठाया था। इस बयान के बाद राज्य की राजनीति में हलचल मच गई।

महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री फडणवीस ने सभी आरोपों को बताया बेबुनियाद फोटो: पीटीआई

शिवसेना नेता अरविंद सावंत ने कहा कि भाजपा ने महाराष्ट्र के साथ गद्दारी की है। उन्होंने कहा कि पार्टी ने राज्य से दुश्मनी निकालने के लिए फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया था, जिसके लिए राज्य की जनता उन्हें माफ नहीं करेगी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) नेता नवाब मलिक ने हेगड़े के बयान के बाद फडणवीस के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा। मलिक ने कहा, 'यह केवल महाराष्ट्र का मामला नहीं है, बल्कि सभी राज्यों के लिए यह खतरे की घंटी है। केंद्र की दोहरी नीति की पोल उसके सांसद ने खोल दी है। प्रधानमंत्री को इस पूरे मामले पर सफाई देनी चाहिए और सभी राज्यों से माफी मांगनी चाहिए।'

हालात बिगड़ते देख फडणवीस इस बयान पर सफाई देने के लिए आगे आए। उन्होंने कहा कि दोबारा मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने कोई भी नीतिगत निर्णय नहीं लिया था। उन्होंने कहा, 'भाजपा और उन पर लगाए जा रहे आरोप पूरी तरह बेबुनियाद हैं। मैं इस बयान से बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि केंद्र ने राज्य के लिए जो रकम भेजी थी, उन्होंने वह वापस कर दी। मैं कुछ दिन के लिए कार्यवाहक मुख्यमंत्री था और उस दौरान मैंने कोई नीतिगत निर्णय नहीं लिए।'

बुलेट परियोजना के संबंध में पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि केवल जमीन अधिग्रहण में उनकी भूमिका है। उन्होंने दावा किया कि केंद्र से कोई रकम नहीं मिली थी और ना ही राज्य का इस परियोजना में कोई योगदान है। फडणवीस ने कहा कि राज्य का वित्त विभाग चाहे तो पूरे मामले की जांच करा सकता है। उन्होंने कहा कि उनकी नजर में बयान देने वाले और इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं लुटाने वाले दोनों ही गलत हैं।

दूसरी ओर, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन समेत राज्य में चल रही सभी विकास परियोजनाओं की समीक्षा के आदेश दिए हैं। बुलेट ट्रेन परियोजना को किसानों और आदिवासियों के कड़े विरोध का सामना करना पड़ा जिनकी भूमि अधिग्रहित की जानी है। ठाकरे ने रविवार देर रात कहा, 'यह सरकार आम आदमी की है। हां, हम बुलेट ट्रेन (परियोजना) की समीक्षा करेंगे। क्या मैंने आरे कार शेड की तरह बुलेट ट्रेन परियोजना को रोका है? नहीं।' ठाकरे ने बताया कि उनकी सरकार राज्य की वित्तीय स्थिति पर श्वेत पत्र भी लाएगी। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार पर करीब पांच लाख करोड़ रुपये का कर्ज है लेकिन वह किसानों का बिना शर्त कर्ज माफ करने को लेकर प्रतिबद्ध है। विधानमंडल में विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री ठाकरे को शपथ लेते समय संविधान के नियामों का पालन न करने का आरोप लगाया, ठाकरे ने शपथ लेते समय छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लिया था जवाब में मुख्यमंत्री ने सदन में कहा कि शिवाजी महाराज हमारे दैवत्य है मैंने उनका नाम लेकर गलत किया तो ऐसी गलती मैं दस जन्म में भी करुंगा। हिन्दुत्व के मुद्दे पर सफाई देते हुए ठाकरे ने कहा कि शिवसेना हिन्दुत्व को कभी नहीं छोड़ सकती है अब भाजपा को विपक्ष में बैठने की आदत डाल लेनी चाहिए।

**उद्धव ठाकरे ने दिए बुलेट ट्रेन समेत राज्य में चल रही सभी विकास परियोजनाओं की समीक्षा के आदेश**

इस बीच, भाजपा में फूट पड़ने की अटकलें तेज हो गई हैं। इसकी शुरुआत भाजपा नेता पंकजा मुंडे के फेसबुक पोस्ट से हुई है। मामला तब और गहरा गया जब पंकजा ने ट्वीटर में अपने ट्वीटर बायो में भाजपा का नाम हटा दिया। पंकजा ने फेसबुक पर लिखा था कि वह अगले कुछ दिनों में आगे का रास्ता चुनने पर निर्णय ले लेंगी। उन्होंने लिखा, 'बदले परिवेश में अपनी ताकत को समझना जरूरी है। मुझे 8 से 10 दिनों तक चिंतन करना है और 12 दिसंबर को आप सभी से पुन: संवाद करूंगी।' पंकजा को विधानसभा चुनाव में परली विधानसभा सीट पर अपने चचेरे भाई धनंजय मुंडे से हार का सामना करना पड़ा था। उनके समर्थक हार के लिए फडणवीस को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। ऐसी अटकलें हैं कि पंकजा शिवसेना का दामन थाम सकती हैं। शिवसेना नेता संजय राउत के एक बयान से इन अटकलों को और तेजी मिल गई है। राउत ने कहा कि भाजपा के 10 से 12 नेता उनकी पार्टी के संपर्क में हैं और वे जल्द शिवसेना आ सकते हैं।

हालांकि महाराष्ट्र भाजपा के अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने ऐसी अटकलों का खंडन किया। उन्होंने कहा कि पंकजा भाजपा की जिम्मेदार नेता हैं और वह पार्टी छोड़ कर कहीं नहीं जाएंगी।

# खाद्य तेल से गाड़ियां भर रहीं रफ्तार

## जोमैटो रेस्त्रां में खाना बनाने के बाद बचे तेल को बायो-डीजल विनिर्माताओं तक पहुंचा रही है

शाइन जैकब

तेल के परिवहन पर नजर रखने के लिए प्रत्येक कंटेनर पर लगाते हैं बार कोड

राजस्थान के 48 वर्षीय ट्रक ड्राइवर काला राम के लिए पिछले दो दशकों से भोजन, पानी और डीजल जिंदगी के अहम पहलू रहे हैं। लेकिन पिछले कुछ महीनों में यह थोड़ा बदला है। वह इन दिनों अपने ट्रक में जिस डीजल का इस्तेमाल कर रहे हैं वह थोड़ा अलग है। काला राम बिज़नेस स्टैंडर्ड से कहते हैं, 'इसका माइलेज थोड़ा कम है लेकिन पिकअप ज्यादा है। मगर लोग बोलते हैं कि ये सबसे शुद्ध है।' वह हरियाणा के बावल में बायो-डीजल बनाने वाली कंपनी बायो-डी एनर्जी के एक रिफिलिंग डिस्पेंसर पर डीजल भरवाने आए थे।

राम जिस ट्रांसपोर्ट कंपनी से जुड़े हैं, उसके मालिक गत अगस्त से ही अपने ट्रकों एवं टैंकरों में बायो-डीजल का इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि राम को भी यह नहीं पता था कि उनके ट्रक में भरा जा रहा बायो-डीजल दिल्ली के रसोईघरों में इस्तेमाल हो चुके कुकिंग ऑयल का ही बदला रूप है। खानपान उत्पादों की आपूर्ति करने वाली कंपनी जोमैटो पुराने कुकिंग ऑयल को इकट्ठा कर बायो-डीजल बनाने वाले विनिर्माताओं तक पहुंचा रही है। रेवाड़ी जिले के बावल में स्थित बायो-डी एनर्जी ऐसी ही बायो-डीजल विनिर्माता है।

बावल से करीब 70 किलोमीटर दूर रेस्टोरेंट श्रृंखला ओम स्वीट्स के मुख्य रसोईघर में चारों तरफ मिठाइयां, नमकीन, बिस्कुट एवं नाश्ते के तमाम व्यंजनों को तैयार किया जा रहा है। करीब 350 कर्मचारी इस रसोईघर में तमाम उत्पादों को तैयार करने में लगे हुए हैं। उसी समय जोमैटो की एक पिकअप रसोईघर के बाहर खड़ी होती है और उसमें इस्तेमाल हो चुके पुराने तेल से भरे कनस्तर भर दिए जाते हैं। फिर यह वैन तेलों से भरे कनस्तर लेकर बायो-डीजल निर्माताओं के कारखाने की तरफ रवाना हो जाती है।

जोमैटो को पुराने खाद्य तेल की आपूर्ति करते हुए ज्यादा दिन नहीं हुए हैं। ओम स्वीट्स के महाप्रबंधक (परिचालन) रजनीश पुरी कहते हैं, 'पहले हम अपने रसोईघरों में इस्तेमाल होने के बाद बचे तेल की आपूर्ति स्थानीय वेंडरों को करते थे। जोमैटो से जुड़ने का फायदा यह है कि इस तेल के गंतव्य के बारे में पूरी जानकारी मिलती रहती है।' वह इस मकसद से बनाया गया एक मोबाइल ऐप दिखाते हैं जिसमें तेल के वजन एवं सफर के बारे में पूरा विवरण देखा जा सकता है। पुराने तेल से पैदा होने वाले स्वास्थ्य खतरों को देखते हुए खानपान श्रृंखलाओं के लिए यह ध्यान रखना बेहद जरूरी है कि उनके यहां इस्तेमाल हो चुके तेल को कहीं और खानपान के लिए तो नहीं इस्तेमाल किया जा रहा है। इस लिहाज से जोमैटो जैसे ऑपरेटर से जुड़ना उन्हें भरोसा दे रहा है। यह बात वैज्ञानिक तौर पर साबित हो चुकी है कि कई बार इस्तेमाल हो चुके तेल में बना खाना खाने से मोटापा, दिल की बीमारी, कैंसर और मधुमेह हो सकता है।

ओम स्वीट्स के रसोईघर में रोजाना करीब 120 लीटर तेल का इस्तेमाल होता है। इसमें पाम ऑयल, देसी घी, सनफ्लॉवर, रिफाइंड और सोया तेल शामिल होते हैं। रसोईघर के प्रबंधक दिनेश यादव कहते हैं, 'हम हरेक दो घंटे पर तेल का गुणवत्ता परीक्षण करते हैं और जरूरत होने पर ताजा तेल डालते हैं। हम हफ्ते में औसतन 450 किलोग्राम तेल जोमैटो को आपूर्ति करते हैं।' अपने घनत्व एवं अशुद्धता की वजह से प्रयुक्त रसोई गैस को लीटर के बजाय किलोग्राम में मापा जाता है। इस्तेमाल के अनुपयुक्त करार दिए जा चुके तेल को कंटेनर में भरने के बाद उन पर बारकोड लगाया जाता है और वैन में भर दिया जाता है। कंटेनर पर लगे बारकोड की मदद से मोबाइल ऐप के जरिये आसानी से नजर रखी जा सकती है।

ओम स्वीट्स के रसोईघर से वैन को हरियाणा के समालखा स्थित जोमैटो गोदाम तक पहुंचने में करीब आधे घंटे लगते हैं। आपूर्ति सहयोगी शिवम कुमार कहते हैं कि कंटेनर को लादने या उतारने के समय केवल ऐप में दिए गए मार्ग का ही अनुसरण किया जाता है। वह कहते हैं, 'रोजाना मैं करीब 15-17 जगहों से तेल इकट्ठा करता हूं।' हालांकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में ऐसे वाहनों के प्रवेश पर लगी समय की पाबंदी से परिचालन में थोड़ी दिक्कत होती है। जोमैटो इस समय दिल्ली-एनसीआर में 1,000 से भी अधिक जगहों से पुराने तेल को इकट्ठा करने का काम कर रही है। इनमें रेस्टोरेंट और छोटे होटलों के अलावा बिरयानी बाइ किलो, यम यम चा, मिठास और बर्कोस जैसे फूड चेन भी शामिल हैं। पुराने तेल के एवज में जोमैटो प्रति किलो 15-32 रुपये का भुगतान भी करती है।

**पुराने तेल के एवज में जोमैटो रेस्टोरेंट को प्रति किलो 15-32 रुपये तक का भुगतान भी करती है**

रसोईघरों से इकट्ठा तेल को समालखा स्थित गोदाम में ले जाया जाता है और वहां पर उसे थोड़ा-बहुत फिल्टर किया जाता है। इसके लिए दस लोगों का स्टाफ रखा गया है। फिलहाल जोमैटो महीने भर में करीब 150 टन तेल इकट्ठा कर रही है जिसके मार्च 2019 तक 1,000 टन तक पहुंच जाने की उसे उम्मीद है। जोमैटो के उपाध्यक्ष (संपोषणीयता) रितेश खेड़ा कहते हैं कि तेल को खानपान की गुणवत्ता के मामले बड़ा दोषी माना जाता है और इस तेल का एग्रीगेटर बनकर कंपनी इसे दूर करने में अपना योगदान दे रही है। हालांकि इस कारोबार में कंपनी को कुछ कमाई भी हो रही है। रसोईघरों से इकट्ठा तेल बायो-डी कंपनी को मामूली मार्जिन पर बेच दिया जाता है।

भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) का कहना है कि बड़े रेस्टोरेंट एवं बड़े रसोईघरों से निकले खराब तेल को छोटे वेंडर खरीदते हैं और उन्हें छोटे दुकानदारों को बेच देते हैं। इस स्थिति में कुछ लोगों को लगता है कि जोमैटो जैसी संगठित कंपनी के इस कारोबार में उतरने से प्रयुक्त खाद्य तेल के प्रबंधन में कुछ हद तक पेशेवर रवैया आएगा। खेड़ा कहते हैं, 'हमारा काम यह सुनिश्चित करना है कि कंटेनर में भरे गए तेल की हरेक बूंद को बायो-डीजल संयंत्र तक पहुंचाया जाए। इस प्रक्रिया में बहुत-कुछ स्वचालित तरीके से होता है।' जोमैटो अब इस कारोबार को अन्य शहरों में भी ले जाने की सोच रहा है। इसके लिए बेंगलूरु स्थित इकोग्रीन फ्युल्स और मुंबई स्थित यूनिकॉर्न के साथ जोमैटो की बातचीत की भी चर्चाएं हैं। इसके अलावा उत्तर भारत के पांच अन्य शहरों में भी वह रसोईघरों से खराब तेल जमा करने का काम शुरू करने वाली है।

जोमैटो समालखा के अपने गोदाम में तेल को तीन चरणों में फिल्टर करती है। इस दौरान तेल में मौजूद अवशिष्ट, पानी एवं फ्री फैटी एसिड (एफएफए) को हटाया जाता है। वहां से उसे बायो डीजल बनाने वाली कंपनी के संयंत्र तक भेज दिया जाता है। बायो-डी की प्रयोगशाला में तैनात इंद्रपाल सिंह कहते हैं, 'हम अपने यहां लाए गए तेल का घनत्व, नमी और आयोडीन मूल्य देखने के बाद ही उसे बड़े भंडार टैंकों में भरते हैं।'

इस संयंत्र की क्षमता रोजाना 100 किलो लीटर तेल की है। वहां पर पुराने तेल को चार चरणों से शोधित किया जाता है जिसमें एफएफए जैसी अशुद्धियों को दूर करना, ग्लिसरीन जैसे उप-उत्पादों को अलग करना और डिस्टिल किया जाता है। करीब 100 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित बायो-डी संयंत्र के निदेशक शिवा विग कहते हैं, 'हमारी खासियत यह है कि यहां तैयार होने वाला तेल डिस्टिल्ड बायो-डीजल होता है जिसे किसी भी डीजल इंजन चालित वाहन में आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है।' राजस्थान के खुदरा बिक्री केंद्रों में यह बायो-डीजल बेचा जाता है। इसके इस्तेमाल से वाहन मालिक को प्रति लीटर तेल पर 2-3 रुपये की बचत होती है।

तेल विपणन कंपनियां गैर-आसवित बायो-डीजल को 51 रुपये प्रति लीटर के तय दाम पर खरीदती हैं। फिर परंपरागत डीजल में पांच फीसदी बायो-डीजल मिलाकर बेचती हैं। जहां तक तैयार बायो-डीजल इस्तेमाल करने वाली कंपनियों का सवाल है तो उन्हें इस पर 10 रुपये प्रति लीटर से भी अधिक फायदा होता है क्योंकि इस पर केवल 12 फीसदी जीएसटी ही लगता है। शायद इसी बात को ध्यान में रखते हुए बायो-डी कंपनी जनवरी में दस खुदरा बिक्री केंद्र भी खोलने जा रही है जिससे काला राम जैसे वाहन चालकों को सीधा लाभ होगा।

# इस्पात उद्योग : घरेलू मांग कमजोर, उत्पादन घटा

## घरेलू मांग कमजोर रहने से छोटी, बड़ी, निजी और सार्वजनिक सभी कंपनियां निर्यात बाजार का रुख कर रही हैं

पृष्ठ 1 का शेष

**इस्को** के पास 6,700 नियमित कर्मचारी हैं जबकि 6,000 कर्मचारी अनुबंध पर हैं। कमलाकर ने कहा, 'उत्पादन भले ही कम हुआ है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमारे कर्मचारी खाली बैठे हैं। कर्मचारियों पर कोई फर्क नहीं पड़ा है।' घरेलू इस्पात उद्योग की करीब 85 फीसदी कोकिंग कोयले की मांग आयात से पूरी होती है। क्रिसिल रिसर्च के मुताबिक इस साल जनवरी से अक्टूबर के दौरान इसकी प्रति टन कीमत 186 डॉलर रही जो पिछले साल की इस अवधि की तुलना में 9 फीसदी कम है। लेकिन इसमें इस्तेमाल होने वाले एक अन्य प्रमुख कच्चे माल लौह अयस्क की कीमत उच्च स्तर पर बनी हुई है।

### हर किसी के पास एक ही समाधान

कमजोर घरेलू मांग के कारण इस्को का जोर निर्यात पर है। इस्को इस मामले में अकेला नहीं है। छोटी और बड़ी, निजी और सार्वजनिक इस्पात कंपनियों की पिछले नौ महीने से यही स्थिति है। अपने माल को खपाने के लिए वे निर्यात बाजार का रुख कर रहे हैं, उत्पादन घटा रहे हैं और तय समय से पहले ही कारोबार समेट रहे हैं।

आंकड़ों के मुताबिक इस वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में तैयार इस्पात की खपत केवल 3.1 फीसदी बढ़ी जबकि पिछले वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में यह 10.3 फीसदी बढ़ी थी।

इक्रा के समूह प्रमुख कॉरपोरेट सेक्टर रेटिंग्स जयंत रॉय इसके लिए कमजोर मांग को जिम्मेदार ठहराते हैं। रॉय ने कहा, 'मांग और कीमतों में कमी से चार बड़ी कंपनियों टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू, जेएसपीएल और सेल के वित्तीय प्रदर्शन पर गहरा असर पड़ा है। वित्त वर्ष 2019 में परिचालन मुनाफा 23 फीसदी से घटकर करीब 18 फीसदी रह गया जबकि इस दौरान ब्याज कवरेज 4.3 गुना से घटकर तीन गुना रह गया। छोटी कंपनियों की वित्तीय स्थिति तो और बदतर रही।'

**नरमी का असर**

जाहिर है कि देश की आर्थिक सुस्ती का असर अब हर जगह दिखने लगा है और इसका प्रभाव लोगों पर विभिन्न तरीकों से दिख रहा है।

मान लीजिए एक प्रमुख निजी इस्पात कंपनी में अधिकारियों का वेरिएबल वेतन करीब 25 से 50 फीसदी है। इसमें 60 फीसदी हिस्सा कंपनी के मानकों से जुड़ा है। इसमें एबिटा भी शामिल हैं। एक अधिकारी ने कहा, 'कंपनी के प्रदर्शन से जुड़ा वेरिएबल वेतन का हिस्सा प्रभावित हो सकता है। अपने खर्च की योजना बनाते समय हमें इस बात का ध्यान रखना होगा।' एकमुश्त राशि का इस्तेमाल अधिकतर महंगी खरीदारी या आवास ऋण के भुगतान में किया जाता है और देश की खपत की कहानी में संभवत: यही पेच है।

### सहायक इकाइयों पर भी पड़ा असर

बड़े इस्पात संयंत्रों से जुड़ी छोटी इकाइयों पर भी सुस्ती का असर साफ देखा जा सकता है। कोलकाता से करीब 15 किमी दूर हावड़ा के औद्योगिक इलाके में स्थित गियरबॉक्स बनाने वाली दो इकाइयां अपना कारोबार बंद कर चुकी हैं। ये इकाइयां जिन कंपनियों को आपूर्ति करती थीं, उन्होंने अब चीन से सस्ते आयात का रुख कर लिया है या स्थानीय स्तर पर खरीदारी कर रही हैं। इसके कारण 300 नौकरियां चली गईं।

नोटबंदी और लागू होने के बाद हावड़ा में पिछले दो-तीन साल में करीब 100 इकाइयां बंद हो चुकी हैं। छोटी इकाइयों के लिए जीएसटी अनुपालन की लागत वहन कर पाना मुश्किल हो रहा था। मांग में सुस्ती ने उनकी कमर तोड़कर रख दी।

हावड़ा चैंबर ऑफ कॉमर्स ऐंड इंडस्ट्री के महासचिव संतोष कुमार उपाध्याय ने कहा, 'ई-वे बिल के कारा कुछ लोगों को सामान को दूसरे राज्यों में भेजना मुश्किल हो रहा है। इसलिए वे उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा का रुख कर रहे हैं या नुकसान उठा रहे हैं और एनसीएलटी में जा रहे हैं।'

स्टील ट्यूब और पाइप बनाने वाली कंपनी पैटन के प्रबंध निदेशक संजय बुधिया ने कहा कि निर्यात पर आधारित 70-75 फीसदी कारोबार सुस्ती के कारण प्रभावित नहीं हुआ है लेकिन वाहन क्षेत्र में सुस्ती के कारण बाकी कारोबार बुरी तरह प्रभावित हुआ है।

रिफ्रैक्टरी कंपनियों पर भी इसका दबाव साफ देखा जा सकता है। इंडियन रिफ्रैक्टरी मेकर्स एसोसिएशन के प्रमुख समीर नागपाल ने कहा, 'पिछले 6 से 9 महीने से साफतौर पर सुस्ती का असर है। इस्पात संयंत्रों में भी उत्पादन उस स्तर पर है सि पर पिछले साल था। कुछ में ज्यादा उत्पादन हो रहा है तो कुछ में कम।'इस्पात संयंत्रों को आपूर्ति करने वाली एक रिफ्रैक्टरी कंपनी के अधिकारी ने कहा, 'हम बहुत कम मुनाफे पर काम कर रहे हैं। ग्राहक देर से भुगतान कर रहे हैं लेकिन भुगतान में कोई छूट नहीं है। इस तरह यह व्यवस्था चरमरा रही है।'

बड़ी इस्पात कंपनियां कीमतें बढ़ा रही हैं जिससे कीमत वसूली के कुछ संकेत हैं लेकिन हर किसी के मन में यह सवाल है कि क्या यह उपाय टिकाऊ है। एक छोटी सहायक इकाई के मालिक ने कहा, 'हम चाहते हैं कि मांग फिर से पटरी पर लौटे।'

### इस्पात उत्पादन

| माह | वृद्धि | माह | वृद्धि |
|---|---|---|---|
| नवंबर 2018 | 5.3 | मई 2019 | 13.3 |
| दिसंबर 2018 | 10.1 | जून 2019 | 10.8 |
| जनवरी 2019 | 5.5 | जुलाई 2019 | 8.1 |
| फरवरी 2019 | 4.9 | अगस्त 2019 | 5.1 |
| मार्च 2019 | 11.5 | सितंबर 2019 | -1.5 |
| अप्रैल 2019 | 13.3 | अक्टूबर 2019 | -1.6 |